RNI No. : TNHIN/2013/5252 ▪ वर्ष - 13 ▪ अंक - 117 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » शुक्रवार » 21-11-2025 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 भारत के लिये हर प्रारूप खेल पाना आसान नहीं : यादव

6 लोकतंत्र की कसौटी पर चुनाव आयोग

7 धनुष के साथ और भी फिल्मों में काम करना चाहती हैं कृति सेनन

फर्स्ट टेक

मणिपुर में सरकार अवश्य होनी चाहिए : भागवत

इम्फाल/भाषा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को कहा कि मणिपुर में सरकार अवश्य होनी चाहिए और सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भागवत ने यहां एक संवाद कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ''सरकार और पार्टियों के मामलों में मैं बहुत हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन मणिपुर में सरकार अवश्य होनी चाहिए और मेरी जानकारी के अनुसार, इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''विनाश होने में दो मिनट का समय लगता है, लेकिन निर्माण में दो साल लगते हैं... और इन कठिन परिस्थितियों में भी, मणिपुर के लोगों को अलग-अलग आधारों पर बिखरने से बचाने के लिए निरंतर प्रयास किये गये... हम निश्चित रूप से सभी को साथ लेकर चलेंगे। किसी की पहचान आदि को नुकसान पहुंचाए बिना, भौतिक मामलों में शांति जल्द स्थापित हो जायेगी, लेकिन आंतरिक शांति आने में कुछ समय लगेगा। हमें इसका ज्ञान है।''

काकेशस पर्वत से खनिज पदार्थ युक्त पानी की भारत में होगी आपूर्ति

मॉस्को/भाषा। दक्षिणी रूस के काकेशस पर्वतों से प्राप्त प्राकृतिक खनिज जल इस वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भारतीय उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा। एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। प्राकृतिक खनिज जल खनिज पदार्थों से युक्त प्राकृतिक जल को कहा जाता है। रूस की कंपनी एक्वा होल्डिंग अमेरिका, कनाडा, चीन, इजराइल और दक्षिण कोरिया सहित दुनिया के 20 से अधिक देशों को काकेशस पर्वत के प्राकृतिक खनिज जल का निर्यात करती है। कंपनी ने पानी की पहली खेप भारत भेज दी है।

बंगाल में फर्जी मतदाताओं की पहचान करेगा एआई

कोलकाता/भाषा। केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान फर्जी मतदाताओं की पहचान करने के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस) आधारित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा। एआई प्रणाली मतदाता डाटाबेस में तस्वीरों का विश्लेषण करके फर्जी मतदाताओं की पहचान करने में मदद करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईओ) कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सॉफ्टवेयर फर्जी फोटो वाले मतदाता का पता लगाने के लिए 'चेहरे की पहचान ' फीचर का इस्तेमाल करेगा।

सूर्यास्त 21-11-2025 5:39 बजे | सूर्योदय 22-11-2025 6:10 बजे

BSE	NSE
85,632.68	26,192.15
(+446.21)	(+139.50)

सोना	चांदी
12,878 रु.	175,000 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

शाही खेल

जब आता मौका चुनाव का,
खेल रहे सब चोर सिपाही।
कभी सिपाही वे बन जाएं,
कभी चोर के वो हमराही।
जीत हार का प्रश्न नहीं है,
सिर्फ समय की आवाजाही।
जनता तो दर्शक है केवल,
खेल सभी का है यह शाही।।

हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं नक्सली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अंबिकापुर/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश भर के नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं तथा केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से निकट भविष्य में ही वामपंथी उग्रवाद का उन्मूलन संभव हो जाएगा।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समाज को दूसरे अन्य समाजों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, ''छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में वामपंथी उग्रवाद का रास्ता छोड़कर लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के सुविचारित और सुसंगठित प्रयासों से निकट भविष्य में ही वामपंथी उग्रवाद का उन्मूलन संभव हो जाएगा। यह एक बहुत ही संतोषजनक बदलाव है।''

राष्ट्रपति ने कहा कि 1.65 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने हाल ही में आयोजित 'बस्तर ओलंपिक' में हिस्सा लिया। यह बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है जनजातीय महानायकों के आदर्शों पर चलते हुए, छत्तीसगढ़ के निवासी सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान देंगे।

मुर्मू ने कहा, ''महिलाएं समाज की धरोहर हैं और जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज आगे बढ़ता है।'

मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारतीय महिला विश्व कप जीतने वाली क्रिकेट टीम के साथ हाल ही में हुई मुलाकात को याद करते हुए आदिवासी महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ की तारीफ की।

लाल किला विस्फोट:

एनआईए ने तीन चिकित्सकों, धार्मिक उपदेशक को हिरासत में लिया

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बृहस्पतिवार को तीन चिकित्सकों और एक धार्मिक उपदेशक को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इन लोगों को 10 नवंबर को लाल किले के निकट हुए कार विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे। विस्फोट के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मुजम्मिल गनई, अदील राथर और शाहीना सईद के साथ-साथ मौलवी इरफान अहमद वागे को गिरफ्तार कर लिया था। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा, ''इन सभी ने आतंकवादी हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।'' उनकी हिरासत एनआईए को सौंपे जाने के साथ ही केंद्रीय एजेंसी द्वारा आरोपित लोगों की संख्या छह हो गई है। एनआईए ने 11 नवंबर को आधिकारिक तौर पर इस मामले को अपने हाथों में लिया था। एनआईए पहले ही दो लोगों आमिर राशिद अली और जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार कर चुकी है।

अब सूडान में गृहयुद्ध समाप्त करेंगे ट्रंप

वाशिंगटन/एपी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह सूडान में जारी भीषण गृहयुद्ध को समाप्त करने में मदद पर अधिक ध्यान देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे इस संबंध में आग्रह किया है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद कई युद्धों को समाप्त कराने का दावा करने वाले ट्रंप ने स्वीकार किया कि क्राउन प्रिंस से बातचीत से पहले यह संघर्ष उनके एजेंडे में शामिल नहीं था।

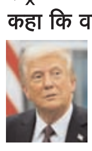

आत्मनिर्भर भारत के लिए

देश की आपदा तैयारी रूपरेखा को मजबूत करने की जरूरत : किशन रेड्डी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर/भाषा। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के 175वें स्थापना वर्ष के मौके पर आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के समर्थन के लिए देश की आपदा तैयारी रूपरेखा को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया।

रेड्डी यहां दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। रेड्डी ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के समर्थन के लिए देश की आपदा तैयारी रूपरेखा को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया।

रेड्डी ने 'अतीत को खोज, भविष्य का निर्माण: जीएसआई के 175 गौरवशाली वर्ष' विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में भारत की वैज्ञानिक तरक्की, औद्योगिक विकास व देश की मजबूती में जीएसआई के योगदान की तारीफ की। उन्होंने जरूरी खनिजों का उत्खनन बढ़ाने, अत्याधुनिक एआई/एमएल आधारित जियो साइंस टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक असित साहा ने संस्थान की 175 वर्ष की विरासत पर प्रकाश डाला।

हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा हमारी साझा ज़िम्मेदारी : डोभाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

▪ हम सहयोग के पांचों स्तंभों के तहत नियमित संवाद के माध्यम से अपनी क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं।

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) की एक बैठक में बृहस्पतिवार को कहा कि समुद्र वह इंजन है जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है और समुद्र के जरिए एक-दूसरे से जुड़े देशों की यह जिम्मेदारी है कि वे हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

सीएससी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की यहां आयोजित सातवीं बैठक में डोभाल ने कहा कि इस महत्वपूर्ण समूह की ताकत और सफलता उसकी साझा सोच, आपसी बातचीत और एक जैसे लक्ष्यों में निहित है। उन्होंने कहा, ''हम सहयोग के पांचों स्तंभों के तहत नियमित संवाद के माध्यम से अपनी क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं।''

डोभाल ने मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत सदस्य देशों के अपने समकक्षों की मेज़बानी की। सेशेल्स ने एक पर्यवेक्षक देश के रूप में जबकि मलेशिया ने अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएससी का गठन सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने तथा हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए साझेदारी को मजबूत करने की खातिर किया गया था।

प्रधानमंत्री मोदी और शाह की मौजूदगी में

नीतीश 10वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री

नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ ली।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को एक भव्य समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री पद की रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस अवसर पर मौजूद थे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कुमार और 26 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यपाल से नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

▪ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कुमार और 26 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''बिहार सरकार में मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई। यह समर्पित नेताओं की शानदार टीम है, जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सभी को मेरी शुभकामनाएं।'' समारोह के अंत में प्रधानमंत्री ने अपने चिरपरिचित अंदाज में 'गमछा' हवा में लहराकर उपस्थित जनसमूह का उत्साह बढ़ाया।

शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान में विशाल मंच तैयार किया गया था, जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की। इनमें आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, असम के हिमंत विश्व शर्मा और दिल्ली की रेखा गुप्ता शामिल थीं।

चीन पाकिस्तान को पनडुब्बियां दे रहा : उप नौसेना प्रमुख

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने बृहस्पतिवार को कहा कि नौसेना को पता है कि चीन पाकिस्तान को पनडुब्बियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि नौसेना स्थिति पर नज़र रख रही है तथा देश की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। नवाचार और स्वदेशीकरण पर आधारित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'स्वावलंबन 2025' से पहले यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह भी माना कि चीन ने अपने तीसरे विमानवाहक पोत 'फुजियान' को नौसेना बेड़े में शामिल कर लिया है।

ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के खिलाफ मामले में 1,400 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों से संबंधित धन शोधन की जांच के तहत 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की हैं। अधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी ने पहले इस मामले में 7,500 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। सूत्रों ने बताया कि देश के विभिन्न भागों में स्थित संपत्तियों के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम कुर्की का यह नया आदेश जारी किया गया है। इस मामले पर अभी रिलायंस समूह से प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सूत्रों ने बताया कि नवीनतम आदेश के तहत 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है।

सम्मान दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु टेक समिट (बीटीएस) 2025 का 28वां संस्करण गुरुवार को बेंगलूरु इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर (बीआईईसी) में संपन्न हुआ, जिसने तीन दिनों के उच्च-प्रभाव वाले नवाचार और वैश्विक सहयोग का इतिहास रचा गया। कर्नाटक सरकार बेंगलूरु टेक समिट 2025 के दौरान फ्यूचर मेकर्स कॉन्क्लेव में अग्रणी स्टार्टअप संस्थापकों को सम्मानित किया जिन्होंने एक अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। समारोह में एक्सेल के पार्टनर प्रशांत प्रकाश, केओनिक्स के चेयरमैन शरत कुमार बच्चे गौड़ा, आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खरगे, सचिव डॉ. मंजुला एन. ने जेप्टो की सहसंस्थापक कैवल्य वोहरा, रैपिड़ो सह संस्थापक पवन गुंटुपल्ली, एथर एनर्जी के सहसंस्थापक स्वप्निल जैन जंबोटेल के सहसंस्थापक एस.कार्तिक वेंकटेश्वरन एवं आशीष जिन्हा, नवी के एमडी और सीईओ राजीव नरेश, ब्लूस्टोन के संस्थापक एवं सीईओ गौरव सिंह खुशवाहा आदि का सम्मान किया गया।

गुरु जयन्तसेनसूरी जन्मभूमि पर हुआ जयन्तसेनसूरी जन्मोत्सव का आयोजन

अनेक धार्मिक व मानवसेवा कार्य आयोजित

पेपराल (गुजरात)। सौधर्म बृहत्तपागच्छीय राजेन्द्रसूरी महाराजा के शिष्य गुरुदेव श्रीमद् विजय जयन्तसेनसूरीश्वरजी म.सा. के 90वें जन्मदिन पर मुनिश्री चारित्ररत्नविजयजी की निश्रा में गुरु जयन्तसेन जन्म भूमि पेपराल तीर्थ पर 18 नवंबर को गुरु जयन्तसेन जन्मोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें गुणानुवाद सभा सहित विभिन्न आयोजन हुए।

कार्यक्रम में थराद, डिसा, अहमदाबाद, लाखणी, वासणा, नारोली, धानेरा, पेपराल सहित त्रिस्तुतिक जैन संघ के अनेक संघ के सदस्य उपस्थित रहे। जयन्तसेनसूरी शासन प्रभावक ट्रस्ट पेपराल तीर्थ आयोजित इस कार्यक्रम में जन्मोत्सव निमित्त गुरु पूजन, पारणा झूलाने का एवं 90 दीप प्रज्ज्वलित करने का लाभ रमेशभाई चंदुलाल परिवार ने लिया एवं गुहंली करने का लाभ प्रवीणकुमार चिमनलाल परिवार ने लिया। गुरुदेव की सुबह की आरती का लाभ रमेशभाई धर्माजी नाई परिवार ने लिया,शाम की आरती का लाभ सवीताबेन मफतलाल संघवी परिवार ने लिया।

कार्यक्रम में पेपराल स्कूल के 300 से अधिक बच्चों ने उपस्थित रहकर नवकार महामंत्र का जाप एवं गुरु भक्ति के गीत गाए,इस प्रसंग पर गुणानुवाद सभा में उपस्थित लोगों ने स्कूल के लिए नगद राशि प्रदान की एवं बच्चों को प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम की पुर्णाहुति पर अखिल भारतीय राजेन्द्र जैन महिला परिषद् शाखा डिसा की ओर बच्चों को मिठाई खिलाई गई। गुरु जन्मोत्सव प्रसंग पर अनेक तपस्वियों ने अठम तप की तपस्या की। कार्यक्रम का संचालन डिसा त्रिस्तुतिक जैन संघ के महामंत्री जगदीश दोशी ने किया।

पंजाब कांग्रेस ने 'वोट चोरी' के खिलाफ 27 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस की पजाब इकाई ने पार्टी के 'वोट चोर-गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान के तहत बुधवार को लगभग 27 लाख हस्ताक्षर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिए और दावा किया कि यह सीमावर्ती प्रदेश 'वोट चोरी' को जरूर रोकेगा। पार्टी महासचिव और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बराड वडिंग तथा विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ये हस्ताक्षर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपे। इस मौके पर बघेल ने संवाददाताओं से कहा कि 'वोट चोर-गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान के तहत पंजाब से करीब 27 लाख आवेदन भरे गए हैं, जिन्हें वेणुगोपाल को सौंपा गया। वडिंग ने आरोप लगाया कि सरकार देश के संविधान में दिए गए वोट के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है। बाजवा ने कहा, ''पंजाब के लोग वोट चोरी को रोकेंगे।''

'भारत में इजराइली कंपनियों के लिए निवेश के बड़े अवसर'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तेल अवीव/भाषा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत में इजराइली कंपनियों के लिए निवेश के काफी अवसर हैं और दोनों देशों के उद्योग बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण और कृत्रिम मेधा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा सकते हैं।

पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्रों में वित्तीय प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, औषधि, अंतरिक्ष और रक्षा शामिल हैं। उन्होंने इजराइल के आर्थिक मामलों के मंत्री नीर बरकत के साथ भारत-इजराइल व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ''दोनों देशों के बीच असीमित संभावनाएं और क्षमताएं हैं।'' यह पहली बार है जब कोई भारतीय वाणिज्य मंत्री इजराइल की यात्रा कर रहा है।

पीयूष गोयल इजराइल में 60 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए नेताओं और कंपनी प्रमुखों से मिलेंगे।

मंत्री ने कहा कि कई ऐसी चीजें हैं जो भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाते हैं। इनमें लोकतंत्र, जनसंख्या संबंधी लाभांश, डिजिटलीकरण, तेज गति विकास और निर्णायक नेतृत्व शामिल हैं।

गोयल ने कहा, ''भारत निवेशकों के अनुकूल और व्यापार के लिए एक भरोसेमंद माहौल प्रदान करता है। यह दोनों पक्षों की कंपनियों के लिए काफी अवसर प्रदान करता है।''

इसी कार्यक्रम में बरकत ने कहा कि भारतीय बुनियादी ढांचा कंपनियां यहां आकर बोली लगा सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत-पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) भी सहयोग बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करता है।

एक अग्रणी पहल के रूप में प्रस्तुत, आईएमईसी का उद्देश्य सऊदी अरब, भारत, अमेरिका और यूरोप के बीच एक विशाल सड़क, रेलमार्ग और पोत परिवहन नेटवर्क स्थापित करना है ताकि एशिया, पश्चिम एशिया और पश्चिम के बीच एकीकरण सुनिश्चित हो सके।

सितंबर, 2023 में दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान आईएमईसी पहल को अंतिम रूप दिया गया था।

इजराइल को भारत का निर्यात 2024-25 में 52 प्रतिशत घटकर 2.14 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले 4.52 अरब डॉलर था। आयात भी 26.2 प्रतिशत घटकर 1.48 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया।

भारत को इजराइल से अप्रैल, 2000 और जून, 2025 के दौरान 33.78 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त हुआ।

दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों की सूची में जल्दी ही और भारतीय बैंक होंगे शामिल : मल्होत्रा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्थिक विस्तार और बैंकिंग प्रणाली में वृद्धि की गति को देखते हुए, भारत के और भी घरेलू बैंक जल्द ही दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों की सूची में शामिल होंगे।

मल्होत्रा ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनमिक्स में वीकेआरवी राव स्मृति व्याख्यान देने के बाद छात्रों से बातचीत में कहा कि आरबीआई भारत के कई बड़े बैंकों को वैश्विक सूची में शामिल नहीं कर सकता। जबकि इसमें उन्हें शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा, ''...सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कई बैंक हैं। जिस गति से वे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि यह केवल समय की बात है कि दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों में हमारे कई बैंक शामिल होंगे।'' वर्तमान में, केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और एचडीएफसी बैंक ही दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल हैं।

ये दोनों बैंक क्रमश: 43वें और 73वें स्थान पर हैं। इस महीने की शुरुआत में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि देश को बड़े और वैश्विक स्तर के बैंकों की जरूरत है और इस संबंध में रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा था, ''यह मौजूदा बैंकों से नए बैंक बनाने से नहीं हो सकता... विलय भी एक रास्ता हो सकता है। सही मायने में आपको एक ऐसे परिवेश की जरूरत है जिसमें ज्यादा बैंक काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। भारत में यह माहौल पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित है, लेकिन मुझे और ज्यादा गतिशील होने की जरूरत है...।''

'रुपए के लिए किसी भी स्तर को लक्ष्य नहीं बनाया, डॉलर की मांग से इसमें गिरावट'

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय बैंक ने रुपए के लिए किसी भी स्तर का लक्ष्य नहीं बनाया है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले घरेलू मुद्रा में हाल में आई गिरावट की वजह डॉलर की मांग में तेजी है।

गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक के पास विदेशी मुद्रा का ''काफी अच्छा'' भंडार है और बाह्य क्षेत्र को लेकर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनमिक्स में वीकेआरवी राव स्मृति व्याख्यान में मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रणाली में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है और केंद्रीय बैंक जहां तक संभव हो, आवश्यक सुरक्षा उपायों एवं सुरक्षा-व्यवस्था को बनाए रखते हुए विनियमनों को सरल बनाने का प्रयास कर रहा है।

डेढ़ गुना बढ़ी टीबी रोगियों की संख्या;2025 तक था बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य : आरटीआई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्र सरकार ने साल 2025 तक तपेदिक (टीबी) रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा था लेकिन देश में पिछले पांच साल में इसके रोगियों की संख्या में डेढ़ गुना वृद्धि दर्ज की गयी है। 2020 में जहां टीबी रोगियों की संख्या 18,05, 670 थी वहीं 2024 में इस संक्रामक रोग का शिकार होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 26,17, 923 हो गयी।

सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत समाचार एजेंसी भाषा द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय क्षय रोग प्रभाग ने यह जानकारी उपलब्ध कराई है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जो 'माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस' नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है। यह रोग मुख्य रूप से रोगी के फेफड़ों को प्रभावित करता है लेकिन शरीर के अन्य अंग जैसे गुर्दे, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। केंद्रीय क्षय रोग प्रभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, टीबी के कुल मामलों की संख्या इस साल अक्टूबर तक 20,77,591 हो चुकी है।

आरटीआई के मुताबिक, 2020 में टीबी के18,05,670, 2021 में 21,35,830, 2022 में 24,22,121, 2023 में 25,52,257 और 2024 में 26,17,923 मामले सामने आए थे। ये आंकड़ें टीबी के मामलों में वृद्धि के परिचायक हैं। प्रति एक लाख आबादी पर टीबी के मामलों की दर की बात की जाए तो यह 2020 में 131, 2021 में 153, 2022 में 172, 2023 में 179, 2024 में 183 और 2025 में 195 पर पहुंच गयी। आरटीआई के तहत केंद्रीय क्षय रोग प्रभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश टीबी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां जून 2025 तक 3,83,987 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 2024 में यहां 6,81,779, 2023 में 6,32,872, 2022 में 5,22,850, 2021 में 4,53,712 और 2020 में 3,66,641 मामले सामने आए थे।

आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जून 2025 तक 62,342 मामले, सामने आ चुके हैं जबकि पिछले चार वर्ष में यह आंकड़ा एक लाख को पार कर गया था। दिल्ली में 2024 में 1,05,343, 2023 में 1,00,523, 2022 में 1,06,731, 2021 में 1,03,038 और 2020 में 86,842 मामले सामने आए थे।

हमारा लक्ष्य मार्च 2026 तक आंध्र को माओवाद-मुक्त बनाना है: डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

राजमुंदरी (आंध्र प्रदेश)/भाषा। आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हरीश कुमार गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि पुलिस केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, मार्च 2026 तक राज्य को माओवाद मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है।

हरीश कुमार गुप्ता ने पूर्वी गोदावरी जिले में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक अधिकांश औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।

साथ ही उन्होंने माओवादी कैडरों से आत्मसमर्पण करने का आह्वान दोहराया और चेतावनी दी कि जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने याद दिलाया

कि आत्मसमर्पण का आह्वान जून में हुई एक मुठभेड़ के बाद किया गया था जिसमें प्रमुख माओवादी मारे गए थे।

गुप्ता ने कहा, हम एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने इस राज्य को मार्च 2026 तक माओवाद मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। राज्य के विकास और सुरक्षित रहने की कामना करते हुए उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश या किसी भी समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।

पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए गुप्ता ने कहा कि उन्होंने राज्य में शरण लेने के लिए घुसे 50 माओवादी कैडरों की गिरफ्तारी में योगदान दिया। इन गिरफ्तारियों के अलावा, पुलिस ने हाल में अल्लूरी सीतारामाराजू जिले के मारेडुमिली मंडल में 13 माओवादियों को ढेर किया था और छह को 18 नवंबर को और सात को 19 नवंबर को मार गिराया। गुप्ता ने यह भी कहा कि इन अभियानों के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री जब्त की गई।

गुप्ता ने उल्लेख किया कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित चार से पांच राज्यों के पुलिस बल मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करने के लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं।

भारत में 5जी ग्राहकों की संख्या 2031 तक एक अरब के पार पहुंचने का अनुमान: रिपोर्ट

नई दिल्ली/भाषा। देश में 2031 के अंत तक 5जी ग्राहकों की संख्या एक अरब के पार पहुंच सकती है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

एरिक्सन मोबिलिटी की यह रिपोर्ट भारत में सेवा के लगातार बढ़ते उपयोग को रेखांकित करती है जहां प्रति स्मार्टफोन मोबाइल डेटा का इस्तेमाल सबसे अधिक है। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रति सक्रिय स्मार्टफोन मोबाइल डेटा इस्तेमाल 2031 तक 65 जीबी प्रति माह तक पहुंचने का अनुमान है जबकि अभी यह वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक 36 जीबी प्रति माह है।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 5जी अपनाने की गति तेजी से बढ़ रही है। 2025 के अंत तक इसके ग्राहकों की संख्या 39.4 करोड़ तक पहुंच जाएगी जो कुल मोबाइल कनेक्शन का 32 प्रतिशत होगी। इसमें अनुमान लगाया गया कि 2031 के अंत तक वैश्विक स्तर पर 5जी ग्राहकों की संख्या 6.4 अरब हो जाएंगी जो सभी मोबाइल कनेक्शन का दो-तिहाई हिस्सा होगा।

एरिक्सन इंडिया के प्रबंध निदेशक नितिन बंसल ने कहा, ''भारत में प्रति सक्रिय स्मार्टफोन मोबाइल डेटा इस्तेमाल 36 जीबी प्रति माह है। यह दुनिया में सबसे अधिक है और 2031 तक इसके बढ़कर 65 जीबी प्रति माह होने का अनुमान है।'' उन्होंने कहा कि 5जी पहले से ही देश में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रूप में काम कर रहा है।

अस्सी प्रतिशत से अधिक दिव्यांग जनों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है : एनजीओ श्वेत पत्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत में 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन बीमा दायरे से बाहर हैं। बृहस्पतिवार को जारी एक श्वेत पत्र में यह जानकारी दी गयी। श्वेत पत्र के अनुसार, कानूनी संरक्षणों के बावजूद बीमा के लिए आवेदन करने वाले आधे से अधिक व्यक्तियों के आवेदन बिना किसी स्पष्टीकरण के ही खारिज कर दिए जाते है।

नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल (एनसीपीईडीपी) द्वारा जारी सभी के लिए समावेशी स्वास्थ्य कवरेज : भारत में स्वास्थ्य बीमा एवं भेदभाव रिपोर्ट को बृहस्पतिवार को एक गोलमेज बैठक में पेश किया गया। इस बैठक में नीति निर्माताओं, बीमा क्षेत्र के प्रतिनिधियों और दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

देशभर के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5,000 से अधिक नमूनों के साथ दिव्यांगजनों पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, अध्ययन में आगाह किया गया है कि गहरी प्रणालीगत असमानताएं अब भी लगभग 16 करोड़ दिव्यांग भारतीयों को सार्वजनिक और निजी दोनों, बीमा योजनाओं से बाहर रखती हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं था, जबकि बीमा के लिए आवेदन करने वालों में से 53 प्रतिशत ने बताया कि उनके आवेदन खारिज कर दिए गए।

उत्तर देने वाले कई लोगों ने बताया कि उन्हें केवल उनकी दिव्यांगता के कारण बीमा देने से इनकार कर दिया गया। ऑटिज़्म, मनोसामाजिक एवं बौद्धिक दिव्यांगता और थैलेसीमिया जैसे रक्त विकारों वाले व्यक्तियों के बीमा के लिए आवेदन अस्वीकृति की दर विशेष रूप से अधिक पाई गई।

रिपोर्ट में कहा गया कि संविधान में दिए गए प्रावधानों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के बार-बार जारी निर्देशों के बावजूद यह स्थिति बनी हुई है।

विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय नहीं की जा सकती: न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती।

शीर्ष अदालत ने अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा कि उच्चतम न्यायालय भी विधेयकों को मंजूरी प्रदान नहीं कर सकता। अपने सर्वसम्मत फैसले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह भी कहा कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत प्रदत्त अधिकारों से परे जाकर विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ''हमें नहीं लगता कि राज्यपालों के पास राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर रोक लगाने की असीमित शक्ति है।'' इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर भी शामिल थे।

उसने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राज्यपालों के लिए समय-सीमा तय करना संविधान द्वारा प्रदत्त लचीलेपन के विरुद्ध है। प्रधान न्यायाधीश ने फैसले का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों के पास तीन विकल्प हैं - विधेयकों को मंजूरी देना, उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना या मंजूरी रोककर अपनी टिप्पणियों के साथ उन्हें विधानसभा को वापस भेजना।

पीठ ने कहा, ''चूंकि संविधान में राज्यपाल के अधिकारों के उपयोग के लिए कोई समयसीमा या उसके इस्तेमाल का तरीका निर्धारित नहीं है, ऐसे में इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत इन अधिकारों के प्रयोग के लिए समयसीमा तय करना उपयुक्त नहीं होगा।'' तमिलनाडु सरकार की याचिका पर निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की अगुवाई वाली पीठ ने इस वर्ष अप्रैल में यह निर्धारित किया था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर तीन महीने में मंजूरी देनी होगी। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उच्चतम न्यायालय के आठ अप्रैल के फैसले पर उठाए गए 14 महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करने पर सहमति जताई।

मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में कुछ कानूनी प्रश्न खड़े हुए हैं जो अपने स्वरूप और सार्वजनिक महत्व के कारण ऐसे हैं कि उन पर न्यायालय की राय लेना आवश्यक हो जाता है। अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार प्रदान करता है।

पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि संवैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल और राष्ट्रपति/राज्यपाल के आदेशों को किसी भी रूप में अनुच्छेद 142 के तहत प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। उसने कहा, ''हम स्पष्ट करते हैं कि संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 142 भी विधेयकों की 'स्वत: स्वीकृति' (डीम्ड एसेंट) की अवधारणा की अनुमति नहीं देता है।'' अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का व्यापक अधिकार देता है। पीठ ने कहा, ''अनुच्छेद 200 का पहला प्रावधान इसके मुख्य प्रावधान से ही जुड़ा हुआ है और किसी चौथे विकल्प की पेशकश करने के बजाय मौजूदा विकल्पों को सीमित करता है। महत्वपूर्ण रूप से तीसरा विकल्प-मंजूरी रोककर विधेयक को टिप्पणियों के साथ वापस भेजना- राज्यपाल के लिए तभी उपलब्ध होता है जब वह वित्त विधेयक न हो।'' उसने कहा कि राज्यपाल इन तीन संवैधानिक विकल्पों में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार रखते हैं और अनुच्छेद 200 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे नहीं होते। उसने कहा, ''अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों का निष्पादन न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता। अदालत ऐसे किसी निर्णय के गुण-दोष की समीक्षा नहीं कर सकती।''

पीठ ने कहा कि यदि राज्यपाल की निष्क्रियता अत्यधिक लंबी, अस्पष्ट और अनिश्चितकाल तक बनी रहे तो ऐसे असाधारण हालात में न्यायालय निर्णय के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, संविधान के तहत राज्यपाल को उचित समय के भीतर अपना दायित्व निभाने के लिए सीमित आदेश जारी कर सकता है। उसने अनुच्छेद 361 का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से न्यायिक कार्यवाही के अधीन करने संबंधी न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसमें कहा गया है, ''हालांकि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की लंबी अवधि तक बनी रहने वाली निष्क्रियता की स्थिति में, इस न्यायालय को प्राप्त सीमित न्यायिक समीक्षा के दायरे को नकारने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।'' पीठ ने स्पष्ट किया कि राज्यपालों को व्यक्तिगत छूट प्राप्त है लेकिन उनका संवैधानिक पद न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

उद्घाटन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

चेन्नई में गुरुवार को सचिवालय में आवास एवं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत चेन्नई महानगर विकास निगम की ओर से 20.89 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हो चुके 4 कार्यों का उद्घाटन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया। जिसमें अवाडी, अन्नानूर और कोनमबेडु सरकारी उच्च विद्यालयों में अतिरिक्त स्कूल भवन, कोयम्बेडु थोक बाजार परिसर में प्रशीतित भंडारण गोदाम, पुझल-मेट्टुपलायम में उन्नत फुटबॉल मैदान और सेतुपट्टू में उन्नत छोटा फुटबॉल मैदान शामिल हैं। इस अवसर पर हिंदू धार्मिक और धर्मस्व मंत्री और चेन्नई महानगर विकास निगम के अध्यक्ष पी.के. शेखरबाबू, मुख्य सचिव एन. मुरुगनांथम, आई.ए.बी., आवास एवं शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती काकरला उषा उपस्थित थे।

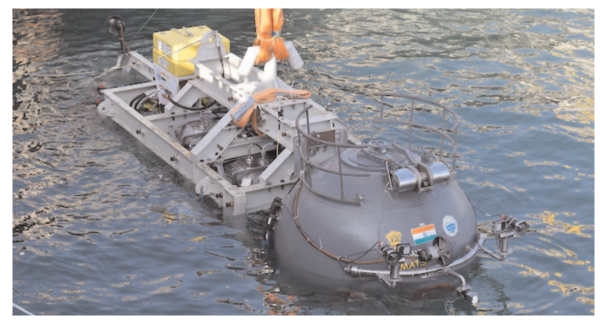

समुद्रयान के जरिये गहरे समुद्र में अन्वेषण करेगा भारत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। अगले वर्ष की शुरुआत में एक शीर्ष समुद्री संस्थान के दो वैज्ञानिक चेन्नई अपतटीय क्षेत्र में 28 टन वजनी स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी (सबमर्जिबल) को 500 मीटर की गहराई तक ले जाएंगे। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के प्रतिष्ठित समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऐसा करने की क्षमता है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) के जल यात्री रमेश राजू और जतिंदर पाल सिंह भारत के डीप ओशन मिशन' के तहत गहरे महासागर के रहस्यों को जानने के लिए 'मत्स्य-6000' का संचालन करेंगे। एनआईओटी के निदेशक बालाजी रामकृष्णन ने यहां पीटीआई-भाषा' से कहा, ''हमने दूर से संचालित यानों का उपयोग करके समुद्र तल की गहराई में अन्वेषण किया है। यह पहली बार है जब हम 6,000 मीटर की गहराई में मनुष्यों को भेज रहे हैं और इस मिशन के लिए सुरक्षा सर्वोपरि है।''

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व वाली भारत की समुद्रयान परियोजना को आत्मनिर्भरता की भावना का भी प्रतिबिंब माना जा रहा है। मानव के साथ गहरे समुद्र में जा सकने वाली पनडुब्बी खरीदने के लिए दो बार वैश्विक निविदाएं जारी की गईं, लेकिन प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं होने के कारण सरकार को इस पोत को देश में ही विकसित करना पड़ा। रामकृष्णन ने कहा, ''हमने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। हमारे पास गहरे समुद्र में गोता लगाने की विशेषज्ञता तो थी लेकिन केवल 1000 मीटर तक। जब हमने परियोजना शुरू की और संबंधित प्रयोगशालाओं का दौरा करना आरंभ किया तो पता चला कि देश के भीतर ही डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) और सीएसआईआर (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) की प्रयोगशालाओं तथा इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) के संस्थानों में आवश्यक विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं।'' वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की गहराइयों में अन्वेषण के लिए मानव को भेजना नयी खोजों की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है क्योंकि वे मौके पर ही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। समुद्रयान परियोजना के निदेशक एस. नारायणन ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''कोई कैमरा मानव नेत्र की बराबरी नहीं कर सकता। उसकी दृष्टि और समझ बिल्कुल भिन्न होती है जो समुद्र तल के बारे में गहन जानकारियां प्रदान करेगी।''

गहरे समुद्र में खनिज, ईंधन एवं जैवविविधता संसाधन मौजूद हैं और केवल अमेरिका, रूस, चीन, जापान एवं फ्रांस जैसे कुछ ही देशों के पास इतनी गहराई में अन्वेषण करने की क्षमता है। 'समुद्रयान' परियोजना की सफलता के साथ भारत भी इन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। 'मत्स्य-6000' पनडुब्बी अगले वर्ष की शुरुआत में वैज्ञानिकों को 500 मीटर की गहराई तक ले जाएगी। यही वह अधिकतम गहराई है जहां तक नौसेना की पनडुब्बियां संचालित होती हैं। भारतीय वैज्ञानिक 2027 में उससे दस गुना अधिक गहराई में गोता लगाने की योजना बना रहे हैं। उसी वर्ष इसरो 'गगनयान' मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने का प्रयास करेगा।

स्टालिन ने धान की नमी के मानदंडों संबंधी अनुरोध खारिज होने पर केंद्र की आलोचना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने धान खरीद के लिए नमी के मानदंडों में ढील देने के राज्य के अनुरोध को खारिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार की बृहस्पतिवार को आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से राज्य के किसानों की सुरक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट' में कहा कि केंद्र ने कावेरी डेल्टा और अन्य जिलों में भारी उत्तर-पूर्वी मानसूनी बारिश के मद्देनजर अधिक नमी वाले धान की खरीद की अनुमति देने के तमिलनाडु के अनुरोध को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा मदुरै के अलावा कोयंबटूर के लिए मेट्रो रेल परियोजना से इनकार किए जाने के बाद बुधवार को ही प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर में एक किसान सम्मेलन में भाग लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के कुछ ही देर बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने धान खरीद में नमी के मानदंडों में ढील देने के हमारे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चालू खरीफ विपणन सत्र के लिए धान में नमी की स्वीकार्य सीमा को मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करने के लिए केंद्र पर दबाव बना रही है। राज्य सरकार का तर्क है कि लगातार बारिश और उच्च आर्द्रता के कारण किसानों के लिए अपनी फसल को पूरी तरह से सुखाना मुश्किल हो रहा है।

स्टालिन ने बताया कि तमिलनाडु में इस सत्र में धान की अच्छी फसल हुई है और मानदंडों में ढील देने से इनकार करने से वे किसान बुरी तरह प्रभावित होंगे जो पहले से ही प्रतिकूल मौसम की मार झेल रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अतीत में राज्य के अनुरोधों पर केंद्र ने धान खरीद के लिए नमी के मानदंडों में ढील दी थी और सवाल किया कि अब इसी तरह की रियायत देने से इनकार क्यों किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, अधिक नमी वाले धान की खरीद की अनुमति देने की तमिलनाडु की अपील प्रधानमंत्री के कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही, किसानों की पीड़ा भरी आवाज क्यों अनसुनी हो रही है? उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कृषक समुदाय के प्रति चिंता का अभाव प्रकट होता है। स्टालिन ने कहा कि जिन किसानों की फसलें बेमौसम बारिश के कारण खराब हुई हैं, उन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहा है और न ही खरीद में नमी की उच्च सीमा की मामूली राहत दी जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि इस तरह के दृष्टिकोण को किसान-हितैषी कैसे कहा जा सकता है। द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नेता ने अपनी मांग दोहराते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह नमी के मानदंडों पर अपने रुख पर तत्काल पुनर्विचार करे, तमिलनाडु के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार करे और ऐसे निर्णय की घोषणा करे जिससे राज्य भर के किसान और लोग आश्वस्त हो सकें।

स्टालिन ने जस्टिस पार्टी के स्थापना दिवस पर आर्यों की 'चालबाज़ी' को नाकाम करने का आह्वान किया

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बृहस्पतिवार को आह्वान किया कि 'साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन' के स्थापना दिवस पर आइए हम आर्यों की सारी चालबाज़ी को नाकाम कर दें।''

'साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन को जस्टिस पार्टी' के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) प्रमुख ने 'एक्स' पर कहा कि यही वह दिन है जब हमारे मातृ संगठन जस्टिस पार्टी की स्थापना गैर-ब्राह्मणवादी घोषणापत्र को लागू करने के लिए की गई थी, ताकि द्रविड़ों को शिक्षा, रोजगार और सत्ता में वाजिब हिस्सा दिलाकर सामाजिक न्याय पक्का किया जा सके। उन्होंने कहा, ''हम साबित कर देंगे कि 'द्रविड़ मॉडल सरकार' (मौजूदा द्रमुक सरकार) जस्टिस पार्टी के विचारों को आगे बढ़ा रही है! आइए हम आर्यों की सारी चालबाज़ी को नाकाम कर दें!'' जस्टिस पार्टी की स्थापना 20 नवंबर 1916 को हुई थी।

राज्यपालों पर न्यायालय का फैसला अच्छा है : द्रमुक

चेन्नई। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने राज्यपालों पर उच्चतम न्यायालय के बृहस्पतिवार के निर्णय को अच्छा फैसला बताया और कहा कि यह राज्यपाल पद की शक्तियों से जुड़े दूसरे मामलों में भी काम आएगा। द्रमुक के वरिष्ठ नेता टीकेएस इलानगोवन ने कहा कि अगर तमिलनाडु के लोगों द्वारा चुनी गई राज्य विधानसभा ने कोई प्रस्ताव पास किया है, तो राज्यपाल को उसे स्वीकार करना होगा।

इलानगोवन ने कहा, अगर उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो संविधान के नियमों के खिलाफ है, तो वे सफाई मांग सकते हैं। वह किसी भी विधेयक को मना नहीं कर सकते। वह यह नहीं कह सकते कि यह विधेयक पारित नहीं हो सकता। उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, यहां तक कि राष्ट्रपति को विधायक और सांसद चुनते हैं। उपराष्ट्रपति को सांसद चुनते हैं। प्रधानमंत्री भी चुने जाते हैं। राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। इसलिए उनका काम यह देखना है कि विधानसभा से पारित किया गया कोई भी विधेयक संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। द्रमुक नेता ने कहा, राज्यपाल किसी विधेयक पर सिर्फ़ स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। वह किसी विधेयक को खारिज नहीं कर सकते। उन्होंने आर एन रवि का ज़िक्र करते हुए कहा, और अगर सरकार कोई सफाई देती है, तो उन्हें उसे मानना होगा। लेकिन यह राज्यपाल अपनी बात पर अड़े हुए हैं। पूर्व सांसद ने कहा, उनका इतिहास रहा है कि वह लोगों के लिए नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है कि वह राजा हैं। वह राजा नहीं हो सकते। राज्यपाल समझें कि लोकतंत्र में किसी राजा की कोई भूमिका नहीं होती। यह एक अच्छा फैसला है और यह राज्यपाल की शक्तियों के बारे में आगे के मामलों में काम आएगा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि यदि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 (विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने की राज्यपाल की शक्ति) के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना विधेयकों को रोकने की अनुमति दी जाती है तो यह संघवाद के हित के खिलाफ होगा।

दक्षिण रेलवे ने पहली बार शुरू की तटीय ट्रेन सेवा

चेन्नई। दक्षिण रेलवे सामाना की तेज और लागत-प्रभावी आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तमिलनाडु और केरल में 'तट से तट' पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का संचालन करेगा। रेलवे द्वारा पहली बार इस तरह की पहल की शुरुआत की गई है। दक्षिण रेलवे द्वारा 19 नवंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस सेवा की विशेषता प्रत्येक गंतव्य के लिए समर्पित पार्सल कोच होना है। विज्ञप्ति के अनुसार यह ट्रेन जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं, उपभोक्ता उत्पाद और औद्योगिक सामग्री सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ले जाने में सक्षम है। साथ ही यह सेवा मंगलूरु सेंट्रल से हर शुक्रवार और चेन्नई के रायपुरम से हर मंगलवार को संचालित की जाएगी। विज्ञप्ति के अनुसार माल लादने और उतारने की प्रक्रिया को सुगम और कुशल बनाने के लिए यह ट्रेन सेवा सलेम, इरोड, उतुक्कुली, तिरुप्पुर, कोयम्बटूर, पलक्कड़, शोरानूर, तिरूर, कोझिकोड, थालास्सेरी, कन्नूर और कासरगोड में रुकेगी। इसमें बताया गया कि 'पार्सल एक्सप्रेस' की पहली सेवा 12 दिसंबर को शुरू होगी। इस दिन ट्रेन मंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन से दोपहर 3.10 बजे रवाना होगी और अगले दिन अपराह्न 1.30 बजे चेन्नई के रायपुरम पहुंचेगी। वापसी के लिए ट्रेन 16 दिसंबर को रायपुरम से अपराह्न 3.45 बजे रवाना होगी।

मुलाकात

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

चेन्नई में सचिवालय में गुरुवार को तमिलनाडु डॉ. जे. जयललिता संगीत और प्रदर्शन कला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त सदस्य मालती लक्ष्मण और सेंथिलदास वेलायुधम ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की।

अन्नाद्रमुक का एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर द्रमुक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

चेन्नई। चेन्नई में विपक्षी दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व अन्नाद्रमुक मंत्री डी जयकुमार ने जहां चेन्नई में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया वहीं पड़ोसी कांचीपुरम में जिलाधिकारी कार्यालय के पास हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री एस एस वैगाईचेलवन ने किया। इस विरोध प्रदर्शन में उथीरामेरुर और श्रीपेरुम्बुदुर क्षेत्रों के अन्नाद्रमुक पार्टी समर्थकों ने भी हिस्सा लिया।

विपक्षी दल ने द्रमुक सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि चल रही एसआईआर अभियान में कथित अनियमितताओं को अंजाम देने के लिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रही है। सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके सहयोगी दलों के कड़े विरोध के बावजूद तमिलनाडु में मतदाता सूची का एसआईआर अभियान चार नवंबर को शुरू हो गया है। अन्नाद्रमुक के कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ़ द्रमुक और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के खिलाफ नारे लगाए और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी नेता जयकुमार ने दावा किया कि सरकार ने बूथ स्तर अधिकारी का कार्य करने के लिए सफाई कर्मचारियों और अन्य अपात्र व्यक्तियों को एसआईआर अभ्यास में लगाया है।

मुलाकात

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

चेन्नई सचिवालय में गुरुवार को ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की महापौर आर प्रिया ने मुख्यमंत्री एम. स्टालिन से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।

सबरीमला मामला : एसआईटी ने पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पद्मकुमार को गिरफ्तार किया

तिरुवनंतपुरम/भाषा। सबरीमला मंदिर से सोना गायब होने के मामले की जांच कर रहे विशेष अन्वेषण दल ने त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अध्यक्ष ए पद्मकुमार को यहां गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पूर्व विधायक से अपराध शाखा के दफ्तर में पूछताछ की गई जिसके बाद दोपहर में उनकी गिरफ्तारी दर्ज की गई। सूत्रों ने बताया कि श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाज़े की चौखट से सोना गायब होने से संबंधित मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद पद्मकुमार को गिरफ्तार किया गया। वह 2019 में टीडीबी के अध्यक्ष थे, जब बोर्ड ने द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों और श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों की चौखट की सोने की परत चढ़ी तांबे की प्लेटें इलेक्ट्रोप्लेटिंग (पॉलिश) के लिए मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार किया था। हालांकि पद्मकुमार ने कहा है कि जब सोने की परत चढ़ी प्लेटें असल में पोट्टी को सौंपी गई थीं, तब वह बोर्ड के अध्यक्ष नहीं थे।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई उत्तर
'यूनियन बैंक भवन', नं. 139, द्वितीय तल, ब्रॉडवे (प्रकासम सलाई) चेन्नई-600108
शुद्धिपत्र
'दक्षिण भारत राष्ट्रमत' समाचार पत्र में 18.11.2025 को प्रकाशित लीज हेतु परिसर की आवश्यकता संबंधी सूचना में, हमारी वर्तमान शाखा - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अलवर थिरु नगर, वलसारवक्कम शाखा, डोर नंबर 115, आर्कोट रोड, वलसारवक्कम, चेन्नई-600087 - से दूरी को प्रकाशित 500 मीटर के स्थान पर 1500 मीटर पढ़ा जाना चाहिए। अन्य विवरण में कोई परिवर्तन नहीं है।
उप महाप्रबंधक

अशोक लेलैंड भारी माल ढुलाई करने वाले ट्रकों की नई श्रृंखला पेश करने की कर रही है तैयारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नईदिल्ली। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड अपनी डीजल ट्रक श्रृंखला का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शेनू अग्रवाल ने कहा कि वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली यह प्रमुख कंपनी अपने अनुसंधान एवं विकास संसाधनों को बेहतर बनाने का काम कर रही है, ताकि बाजार में आने में लगने वाले समय को कम किया जा सके और बदलती बाजार एवं नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को तेजी ढाला जा सके।

अग्रवाल ने विश्लेषकों के साथ बातचीत में कहा, ''डीजल श्रृंखला में हम जल्द ही 320 और 360 हॉर्सपावर की पावर रेटिंग वाले 'हेवी-ड्यूटी ट्रक' (भारी माल ढुलाई करने वाले) की एक पूरी तरह से नई श्रृंखला पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। ये नए ट्रक उन्नत 'हेवी-ड्यूटी एग्रीगेट्स' से बने हैं जो बेजोड़ विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।'' इन उत्पादों में छह सिलेंडर इंजन लगाए जाएंगे जो संबंधित खंडों में वाहनों को घुमाने की उच्चतम क्षमता (पीक टॉर्क) प्रदान करेंगे जिससे इस श्रेणी के ग्राहकों को कम समय में अधिक

फेरे लगाने का मौका मिलेगा और इस प्रकार प्रति माह अधिक आय होगी। अग्रवाल ने कहा कि कंपनी का गैर-डीजल खंड लगातार बढ़ रहा है जिसमें हल्के इलेक्ट्रिक ट्रक के दो मॉडल, एमएचसीवी इलेक्ट्रिक ट्रक के तीन मॉडल और इलेक्ट्रिक बसों के कई मॉडल एवं संस्करण पहले से ही व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं। कंपनी ने सीएनजी, एलएनजी और यहां तक कि हाइड्रोजन जैसी अन्य हरित प्रौद्योगिकियों में भी प्रवेश किया है। अग्रवाल ने कहा, ''हम पूरी तरह से निर्मित बसों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी तरह से निर्मित बस क्षमता में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। लखनऊ स्थित हमारे नवीनतम एवं सबसे आधुनिक बस संयंत्र का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश और लखनऊ स्थित हमारे संयंत्रों के पूर्ण विस्तार के बाद हमारी बस का ढांचा बनाने (बॉडी-बिल्डिंग) की वर्तमान क्षमता लगभग 12,000 से बढ़कर 20,000 से अधिक प्रति वर्ष हो जाएगी।'' चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही पर उन्होंने कहा कि कंपनी मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहन (एमएचसीवी) तथा हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) दोनों खंडों के लिए वाणिज्यिक वाहन उद्योग की वृद्धि संभावनाओं के बारे में आशावादी बनी हुई है।

अग्रवाल ने कहा, ''जीएसटी दरों में कटौती से एलसीवी खंड में पहले ही तेजी आ चुकी है। हमारा मानना है कि व्यापक खपत में वृद्धि एवं बुनियादी ढांचा गतिविधियों में वृद्धि से एमएचसीवी उद्योग दूसरी छमाही में भी तेजी से आगे बढ़ेगा।'' जीएसटी सुधारों पर उन्होंने कहा कि 28 से 18% तक की दर को युक्तिसंगत बनाने से नए ट्रक और बस के स्वामित्व की लागत में कमी आई है।

தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம்
तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय
CENTRAL UNIVERSITY OF TAMIL NADU
(Established by an Act of Parliament, 2009)
☎: 04366-277359, 04366-277432 | ईमेल/email: purchase@cutn.ac.in

டெண்டர் அறிவிப்பு / निविदा सूचना / TENDER NOTICE

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை (DST) – இந்தியப் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவியலின் சிறப்பை மேம்படுத்துதல்(PURSE) திட்டத்தின் கீழ் முப்பரிமாண உயிரி அச்சாக்க ஆய்வகக் கருவி வழங்குவதற்கும் நிறுவுவதற்கும் உற்பத்தியாளர்கள் / நிறுவனங்களிடமிருந்து நிதிசார்ந்த பகுதி தொழில்நுட்பப்பகுதி என இரு பகுதிகளாக முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. ஒப்பந்தப் புள்ளி எண்:CUTN/PUR/ 2025-26/07. மேலதிக விவரங்களுக்கு www.cutn.ac.in/tenders (அல்லது) CPP Portal
डीएसटी-पर्स परियोजना, निविदा संख्या CUTN/PUR/2025-26/07, के अंतर्गत प्रयोगशाला उपकरण- 3डी बायोप्रिंटिंग सुविधा की आपूर्ति एवं संस्थापन हेतु प्रतिष्ठित निर्माता/फर्मों से दो-बोली प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। कृपया अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cutn.ac.in/tenders या CPP पोर्टल देखें।
Tenders are invited online under TWO BID SYSTEM from reputed manufacturer / Firms for SUPPLY AND INSTALLATION OF LABORATORY INSTRUMENTS 3D BIOPRINTING FACILITY UNDER DST – PURSE PROJECT, Tender No. CUTN/PUR/2025-26/07, please (Refer the University website www.cutn.ac.in/tenders or CPP Portal for more details)
Sd/-
cbc21299/12/0009/2526
பதிவாளர் / कुलसचिव /REGISTRAR

वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए प्रेरित करता है : मीना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। वंदे मातरम गीत ने देश के क्रान्तीकारियों को देश प्रेम एवं देश को आजादी दिलाने के लिए प्रेरित किया। इस गीत के 150 साल होने के बाद भी आज भी हम गाते है तो स्वतः ही राष्ट्रभक्ति के भाव पैदा हो जाते है। यह विचार गुरूवार को केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर की ओर से शहीद कैप्टन रिपुदमन राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर के सभागार में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने व्यक्त किए। प्रारम्भ में मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने प्रदर्शनी का फीता काटकर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत रूप से प्रदर्शनी का उदघाटन किया।अवसर था भारत का गणतंत्र–एक सुनहरी यात्रा एवं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 बर्ष ,भारतीय सविंधान की 75 बर्ष की यात्रा विषयों पर केंद्रित दो दिवसीय मल्टी मीडिया प्रदर्शनी के उदघाटन का।

कृषि मंत्री ने कहा की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में देश की आजादी से लेकर आज तक देश में सरकारों द्वारा किये गये विकास कार्यो एवं उपलब्धीयों को बेहतर तरिके से दर्शाया गया है। उन्होने कहा कि इस प्रदर्शनी में भारत का गणतंत्र–एक सुनहरी यात्रा एवं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 बर्ष ,के साथ–साथ भारतीय सविंधान की 75 बर्ष की यात्रा को अनेक माध्यमों से प्रस्तुत किया है ।

उन्होने छात्र/छात्राओं से कहा कि इस प्रदर्शनी में दी गई जानकारी को ग्रहण कर उनसे फायदा उठाये। उन्होंने कहा कि हमारे देश का संविघान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें देश के सभी वर्गो को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी गई है लेकिन संविधान में कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किये है, उनकी पालना करना हम सभी का परम कर्तव्य है। प्रदर्शनी के दौरान भारत का गणतंत्र –एक सुनहरी यात्रा एवं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 बर्ष ,भारतीय सविंधान की 75 बर्ष की यात्रा विषयों पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिनमें स्कूली विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम के अंत में इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भी आमजन को अपने विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में विभाग के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत का गणतंत्र–एक सुनहरी यात्रा एवं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 बर्ष ,भारतीय सविंधान की 75 बर्ष की यात्रा पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृखंला में गुरूवार को राजकीय महाविधालय में जागरूकता रैली निकाली गई।

जीसीसी के आवेदनों का होगा त्वरित निस्तारण : भजनलाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में अनुमोदित राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी–2025 प्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) का पसंदीदा गंतव्य स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों का सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम और किफायती ऑपरेशनल लागत के साथ–साथ इस नीति के अंतर्गत सब्सिडी के प्रावधान इच्छुक कंपनियों को राजस्थान में जीसीसी की स्थापना के लिए आकर्षित करते हैं।

सुदृढ़ बुनियादी ढांचा, कुशल कार्यबल और निवेश अनुकूल नीतियों की विशेषताओं के साथ प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में गत दो वर्ष में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट–2024 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, जिनमें से लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी हैं। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं। प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं। एनसीआर रीजन और दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के साथ कनेक्टिविटी राजस्थान में जीसीसी निवेशकों की पहुंच बड़े औद्योगिक केन्द्रों और बाजारों तक उपलब्ध कराती है। साथ ही, देश के बड़े शहरों की तुलना में यहां प्रमुख शहरों में साधनों एवं सेवाओं की किफायती ऑपरेशनल लागत भी निवेश को सुगम बनाती है।

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी–2025 में जीसीसी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। इच्छुक आवेदकों को राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन कमेटी (पीईसी) इन आवेदनों की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा प्राथमिकता से 60 दिन की समय सीमा में प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (पीएसी) को प्रस्तुत करेगी। यह अप्रूवल कमेटी भी 60 दिन की समय सीमा में अनुशंसा के आधार पर आवेदन पर निर्णय करेगी। कार्यकारी निदेशक रीको, पीईसी और प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पीएसी के अध्यक्ष होंगे। जीसीसी के आवेदनों के निस्तारण के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

जीसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नवाचार, दक्षता और मूल्य सृजन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं। ये केंद्र प्रौद्योगिकी, वित्त, मानव संसाधन, अनुसंधान और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने के साथ ही स्थानीय प्रतिभा को प्रशिक्षित करने का कार्य भी कर रहे हैं। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी–2025 वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है।

पत्नी की खुदकुशी के बाद पति ने बेटे को मारा, फिर खुद भी फंदे पर झूला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

उदयपुर। जिले के मसारो की ओवरी गांव में गुरुवार सुबह ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया कि पूरा इलाका सन्न रह गया। एक ही घर में पति–पत्नी और 7 साल के मासूम बेटे की लाशें मिलीं। दरवाज़ा अंदर से बंद था और बाहर खड़ी जगदीश की बाइक कुछ अनहोनी का संकेत दे रही थी। जब माता–पिता रिश्तेदारी से लौटकर आए और गेट नहीं खुला तो गांव के लोग जुटे, गेट तुड़वाया गया और भीतर जो देखा गया, उसने हर किसी की आंखें नम कर दीं। फर्श पर 27 साल की शारदा का शव पड़ा था। उसके कुछ कदम दूर ही दूसरे कमरे में 7 साल का हेमांशु उर्फ हेमू फंदे से लटका मिला। उसी कमरे में 30 वर्षीय जगदीश की लाश भी फंदे से लटकी थी। घर की दीवार पर एक सुसाइड नोट चिपका था, जिसमें लिखा थामेरे घरवालों की कोई गलती नहीं है। मैं खुद मर रहा हूं। हेमू की मम्मी मेरे से पहले फंदा लगाकर मर गई थी। कोई भी मेरे मां–बाप को परेशान न करे। ये मरी, इसलिए हम दोनों भी मरे हैं। डीएसपी राजीव राहर बताते हैं कि घटना बुधवार शाम करीब 7 बजे की है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि जगदीश काम से घर लौटा तो पत्नी का शव फंदे से लटका मिला। उसने उसे नीचे उतारा और फर्श पर रखा। इसके बाद उसने अपने बेटे को दूसरे कमरे में ले जाकर फंदे पर लटका दिया और उसकी मौत होने के बाद खुद भी फंदे से झूल गया। अभी पत्नी के आत्महत्या करने की वजह साफ नहीं है। शारदा का पीहर और जगदीश का परिवार दोनों ही पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

शारदा के भाई प्रकाश ने थाने में रिपोर्ट देकर कहा है कि यह हत्या है या सुसाइड, पुलिस सच्चाई सामने लाए। वहीं जगदीश के छोटे भाई सुनील ने भी जांच की मांग की है। पुलिस ने सभी शवों को ऋषभदेव हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में रखवाया है और सुसाइड नोट, मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और परिवार की परिस्थितियों की गहराई से जांच की जा रही है। गांव के लोग सदमे में हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा परिवार खत्म हो गया। घर के बाहर रोते–बिलखते परिजनों के बीच सिर्फ एक सवाल गूंज रहा हैआखिर कौन–सी ऐसी दरार थी, जिसने एक मां की जान ली, फिर एक पिता को हिला दिया, और जिसकी कीमत एक मासूम बच्चे को भी अपनी सांसों से चुकानी पड़ी?

जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में वायुसेना का टूटा हुआ ड्रोन मिला

जैसलमेर।राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामगढ़ सीमावर्ती इलाके में भारतीय व ायुसेना का टूटा हुआ ड्रोन पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। रामगढ़ थाने के सहायक उपनिरीक्षक प्रेम शंकर ने बताया कि यह ड्रोन चक नंबर तीन, सत्तार माइनर के एक खेत में मिला। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची व मामले की जांच शुरू की हालांकि बाद में भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया।

उदयपुर में दंपति व नाबालिग बेटे का शव घर से बरामद

जयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में दंपति और उनके सात साल के बेटे का शव बुधवार शाम उनके ही घर से बरामद किया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पति जब घर लौटा तो उसकी पत्नी फर्श पर मृत पड़ी थी, इसके बाद उसने अपने सात साल के बेटे को फंदे से कथित तौर पर लटका दिया और खुद भी फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, घर में एक 'सुसाइड नोट' मिला है। पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार को ऋषभदेव थानाक्षेत्र के मसारो की ओवरी गांव में हुई। पुलिस उपाधीक्षक राजीव राहर ने बताया कि महिला के आत्महत्या करने का कारण अभी पता नहीं चला है। उन्होंने बताया, मौत के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, शारदा (27) फर्श पर मृत पड़ी मिली जबकि उसका पति जगदीश (30) और उनका बेटा हिमांशु उर्फ हेमू (सात) अलग–अलग कमरों में फंदे से लटके हुए पाये गये। पुलिस ने बताया कि जगदीश पेट्रोल पंप पर काम करता था जबकि शारदा ने हाल ही में एक निजी क्लिनिक में काम करना शुरू किया था। पुलिस के मुताबिक, जगदीश के माता–पिता पास के गांव गए थे और बुधवार शाम लौटे तो घर अंदर से बंद मिला, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा गया।

शेखावाटी इलाके में सर्दी बढ़ी

जयपुर। राजस्थान के कई हिस्सों विशेष रूप से शेखावाटी इलाके में सर्दी बढ़ गई है, जहां न्यूनतम तापमान लगभग छह डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, बीती रात फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस और नागौर में 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसने बताया कि राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा लेकिन यह अब भी सामान्य तापमान से 3–4 डिग्री सेल्सियस कम है। इसके अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 10 दिन के दौरान मौसम शुष्क रहने तथा तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। हालांकि, दक्षिणी भागों में पूर्वी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी (1–2 डिग्री सेल्सियस) हो सकती है।

जयपुर में युवा कांग्रेस और पुलिस आमने-सामने : सीएम आवास मार्च रोका, बैरिकेड्स पर चढ़े कार्यकर्ता

जयपुर। पूनिया बोलेसरकार से आम आदमी परेशान जयपुर। जयपुर में गुरुवार को युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इसी दौरान कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और बैरिकेड्स पर चढ़ने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तेज धक्का–मुक्की हुई। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी, बदहाल कानून व्यवस्था, और फसल खराबे का मुआवज़ा न मिलने से जनता त्रस्त है। इसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में युवा कांग्रेस सड़क पर उतरी और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की।

कांग्रेस नेता अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि सरकार से आम आदमी परेशान है। कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा छापेमारी तो कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं नजर नहीं आती। उन्होंने ङखठ को लेकर उठे विवाद और इडज द्वारा आत्महत्या की घटना पर भी सरकार को घेरा। पूनिया ने सवाल उठाया कि क्या 20–25 दिनों में पूरे राजस्थान की ङखठ कराना संभव है? प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी विकास छिकारा, सह–प्रभारी ज्ञानेश शुक्ला, प्रदेशाध्यक्ष और संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, सहित युवा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

राजस्थान विधानसभा होगी और अधिक डिजिटलः अब विधायक करेंगे डिजिटल हस्ताक्षर

जयपुर। राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण अब डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। विधानसभा की समितियों को बैठकों में विधायकगण आईपैड पर स्टाइलस पेन की सहायता से डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की यह पहल विधान सभा को डिजिटल बनाये जाने की दिशा में नया कदम है। देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा में डिजिटल हस्ताक्षर की यह नई व्यवस्था आगामी एक दिसम्बर से आरम्भ होगी। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की डिजिटल सदन की पहल राजस्थान विधानसभा के आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस व्यवस्था के तहत सदन की कार्यसूची, प्रश्नोत्तर, विधेयक, ध्यानाकर्षण और शून्यकाल से संबंधित सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं।

सिविल लाइंस इलाके में घुसा तेंदुआ पकड़ में आया

जयपुर। जयपुर के उच्च सुरक्षा वाले सिविल लाइंस इलाके में घुसे तेंदुए को वन कर्मियों ने बेहोश (ट्रैंक्यूलाइज) कर पकड़ लिया। इससे पहले तेंदुए घूमता नजर आने पर इलाके में दहशत फैल गई थी। यह तेंदुआ एक स्कूल और एक कैबिनेट मंत्री के सरकारी बंगले समेत आसपास के क्षेत्र में घूमता हुआ देखा गया था।

अधिकारियों ने बताया कि तेंदुआ सबसे पहले टाइनी ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में घुसता हुआ देखा गया, जिसके बाद वहां के स्टाफ ने एहतियात के तौर पर विद्यार्थियों को कक्षाओं में बंद कर दिया।

इससे पहले यह तेंदुआ कथित तौर पर राज्य के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले में घुस गया था। मंत्री का बंगला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के घर के सामने है। सिविल लाइंस इलाके में राजभवन, मुख्यमंत्री का आवास और कई मंत्रियों तथा बड़े अधिकारियों के सरकारी आवास भी हैं।

कांग्रेस धर्म परिवर्तन कराने वालों के साथ खड़ी, डोटासरा की मानसिकता हिन्दू विरोधी : जवाहर सिंह बेढम

जयपुर। गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक का कठोर कानून बनाया है। जिसके माध्यम से डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने अपने कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को इस विधेयक की विरोध करने की जो बात कही है, उससे लगता है कि वो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों का परोक्ष रूप से समर्थन करते है।

गोविंद डोटासरा की मानसिकता ही हिन्दू विरोधी है और हम डोटासरा के इन मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। बेढम ने कहा कि धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाएं, मिशनरीज लोग लोगों को प्रलोभन देकर, शादी का झांसा देकर, इलाज का लालच देकर, डराकर, धमकाकर धर्म परिवर्तन का काम करते है। पहले लचीला कानून बनाया गया था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इसके खिलाफ सरकार द्वारा कठोर कानून लाया गया।

मोकलसर में हर्षोल्लास से सम्पन्न हुई सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ प्रतिष्ठा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मोकलसर। मोकलसर नगर में मूलनायक परमात्मा सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ आदि जिन प्रतिमाओं की एवं ऊपर के गर्भगृह में मूलनायक श्री अजितनाथ भगवान आदि जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 16 नवम्बर को हर्षोल्लास के साथ आचार्यश्री जिनकान्तिसागर सूरीश्वरजी म.सा. के शिष्य खरतरगच्छाधपिति आचार्य श्री जिनमणिप्रभसूरीश्वरजी की निश्रा में संपन्न हुई। गणिवर्य श्री मयंकप्रभसागरजी की निश्रा में कुंभ स्थापना, दीप स्थापना, ज्वारारोपण, क्षेत्रपाल स्थापना के साथ पार्श्वनाथ पंचकल्याणक पूजा पढाई गई। उसके बाद अठारह अभिषेक, नवग्रह पूजन, दशदिक्पाल पूजन व अष्ट मंगल पूजन के साथ पंच परमेष्ठी पूजा पढाई गई। रविवार को शुभ मुहूर्त में परमात्मा को गादीनशीन किया गया।

चार सौ से अधिक वर्ष प्राचीन मूलनायक सहसफणा पार्श्वनाथ परमात्मा को विराजमान करने का लाभ बबुबाई लालचंद गुलेच्छा परिवार, दायीं ओर पार्श्वनाथ प्रभु विराजमान का लाभ भंवरलाल मोतीलाल पालरेचा परिवार ने, बायीं ओर पार्श्वनाथ प्रभु विराजमान का लाभ दीपचंद मदनलाल अशोककुमारजी बाफना परिवार ने लिया। ऊपर के गर्भगृह के मूलनायक श्री अजितनाथ प्रभु को विराजमान का लाभ भंवरलाल मोतीलाल पालरेचा परिवार ने, चंद्रप्रभ भगवान का लाभ संघवी शांतिदेवी पुखराज गुलेच्छा परिवार ने, सुमतिनाथ प्रभु का लाभ शांतिदेवी चुन्नीलाल गुलेच्छा परिवार ने, वासुपूज्य प्रभु को विराजमान का लाभ भंवरीबाई छगनलाल बाफना ने, कुंथुनाथ प्रभु का लाभ सीतादेवी गुणेशमल बाफना परिवार ने लिया। द्वारोद्घाटन का लाभ सीतादेवी गुणेशमल बाफना परिवार ने लिया।

राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह से पहले सरयू घाट से शुरू हुई कलश यात्रा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अयोध्या/भाषा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण से पहले बृहस्पतिवार को सरयू घाट से कलश यात्रा शुरू हुई।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने शोभायात्रा शुरू होने से पहले सरयू तट पर कलश पूजन किया, जिसके बाद महिला श्रद्धालुओं ने 551 कलश लेकर राम पथ पर यह यात्रा शुरू की।

मंदिर परिसर के आसपास के रामकोट क्षेत्र की परिक्रमा पूरी करने के बाद यह यात्रा राम जन्मभूमि परिसर पहुंची।

मंदिर के पदाधिकारियों ने बताया कि कलश यात्रा के दौरान एकत्र होने वाले जल का इस्तेमाल राम मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण से पहले होने जा रहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाएगा। ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल होंगे।

बिहार सरकार प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम करेगी : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

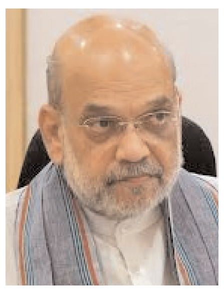

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा कि यह 'डबल इंजन' सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए और अधिक ऊर्जा से कार्य करेगी।

शाह ने उपमुख्यमंत्रियों और सभी मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी।

शाह ने 'एक्स' पर पोस्ट किये गये एक संदेश में कहा कि 20 वर्षों से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा किए जा रहे विकास और सुशासन पर विश्वास जताने के लिए बिहार की जनता का आभार। उन्होंने कहा, ''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को शपथ लेने पर हार्दिक शुभकामनाएं।''

शाह ने कहा, ''यह 'डबल इंजन' सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित बिहार' के दृष्टिकोण को साकार करने और समाज के सभी वर्गों तक विकास के कामों को पहुंचाने के लिए और भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करेगी।''

जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को एक भव्य समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री पद की रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह समेत कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, ''आज पटना के गांधी मैदान में बिहार के कोने-कोने से लाखों की संख्या में आकर राजग सरकार को प्रदेशवासियों का आशीर्वाद देना बताता है कि यह बिहार के जन-जन की सरकार है। बिहार के सभी लोगों को दिल से बधाई।''

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस अवसर पर मौजूद थे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कुमार और 26 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

नीतीश कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यपाल से नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

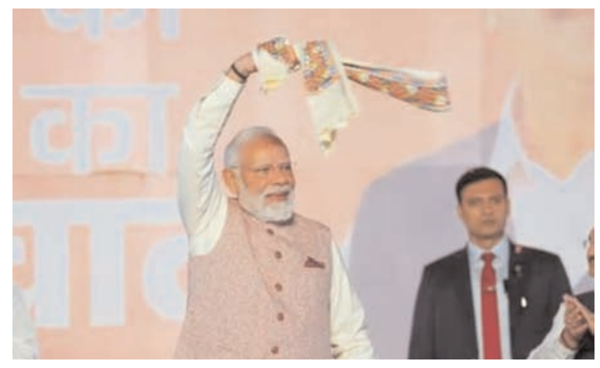

शपथ ग्रहण समारोह में मोदी का 'गमछा' लहराना बना आकर्षण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'गमछा' लहराना भीड़ के आकर्षण का केंद्र रहा।

जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा लहराया, गांधी मैदान में मौजूद करीब तीन लाख लोगों की भीड़ में उत्साह का माहौल बन गया।

कार्यक्रम में कलाकारों ने लोकगीतों और लोकनृत्यों की प्रस्तुति देकर मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों का मन मोह लिया। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार द्वारा रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ पूरी करते ही प्रधानमंत्री ने भीड़ की ओर 'गमछा' लहराया, जिससे देर तक तालियों की गूंज सुनाई देती रही। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। सबसे पहले 'सामा-चकवा' की रंगारंग प्रस्तुति हुई, जो मिथिला क्षेत्र का लोकप्रिय लोकनृत्य है और भाई-बहन के प्रेम का उत्सव माना जाता है।

महिला कलाकारों के एक समूह ने यह नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों की महिला कलाकारों ने अलग-अलग क्षेत्रों के गीत और नृत्य प्रस्तुत किए।

अमेरिकी संसद की रिपोर्ट भारत के लिए एक और कूटनीतिक झटका : कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने अमेरिका संसद से संबंधित एक रिपोर्ट में कथित तौर पर उल्लेखित कुछ बातों का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि यह भारत की कूटनीति के लिए एक और बड़ा झटका है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस की यह रिपोर्ट भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है।

रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, ''अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग ने हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी है। अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा संयुक्त रूप से गठित आयोग में 12 स्वतंत्र सदस्य हैं। उन्होंने कहा, ''2025 की वार्षिक रिपोर्ट लगभग 800 पृष्ठों की है। पृष्ठ 108 और 109 के अनुभाग बिल्कुल आश्चर्यजनक और समझ से परे हैं।'' रमेश ने दावा किया कि इस रिपोर्ट में अप्रैल 2025 में पाकिस्तान द्वारा कराए गए पहलगाम आतंकी हमले को 'विद्रोही हमला' बताया गया है तथा चार दिवसीय संघर्ष में 'भारत पर पाकिस्तान की सैन्य सफलता' की बात की गई है।

कांग्रेस नेता ने कहा, (अमेरिकी) राष्ट्रपति (डोनाल्ड) ट्रंप ने (अब तक) 60 बार दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिन्दूर को रूकवाया। प्रधानमंत्री ने (इस पर) पूरी तरह चुप्पी साध रखी है।

रमेश का कहना था कि अब अमेरिकी कांग्रेस के अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा आयोग की यह रिपोर्ट आई है जो भारत के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर आपत्ति और विरोध दर्ज कराएंगे?

रमेश ने दावा किया कि देश की कूटनीति को एक और करारा झटका लगा है। उन्होंने ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता संबंधी दावा एक बार फिर किए जाने का हवाला देते हुए सरकार पर कटाक्ष किया। रमेश ने कहा, ''अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गठित एक स्वतंत्र आयोग की रिपोर्ट जारी होने के कुछ ही घंटों बाद-जिसमें दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 'भारत पर सैन्य सफलता हासिल की'-अमेरिका के राष्ट्रपति ने 61वीं बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत पर 350 प्रतिशत टैरिफ (शुल्क) लगाने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर को खत्म कराया था।''

दो विधायकों का मंत्री बनना पिता रामविलास के सपने का सच होना: चिराग पासवान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा)-रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार की नई सरकार में उनकी पार्टी के दो विधायकों को जगह मिलना एक बड़ी जीत है, जिसका सपना उनके दिवंगत पिता राम विलास पासवान ने लंबे समय तक देखा था।

चिराग ने कहा कि चुनावी जनादेश ने पार्टी पर विकसित बिहार की दिशा में काम करने की बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, आज का दिन राम विलास पासवान जी को याद करने का है और बिहार को विकसित बनाने के लिए काम करने का है। यह बड़ा दिन है और इस दिन मैं सबसे पहले अपने नेता व पिता माननीय राम विलास पासवान जी को याद करता हूं। लोजपा (रामविलास) ने विधानसभा चुनाव में 19 सीट पर जीत हासिल की, जिनमें से संजय कुमार और संजय कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को मंत्री पद की शपथ ली। चिराग ने कहा, मुझे पता है कि आज वह (राम विलास पासवान) सबसे ज्यादा खुश होते, जिस ऊंचाई पर वह हमारी पार्टी को देखना चाहते थे, आज पार्टी वहां पहुंची है। आज हमारी पार्टी के दो मंत्रियों ने शपथ ली। परिणाम बताते हैं कि पार्टी ने निश्चित रूप से बड़ी जीत हासिल की है। और मेरा मानना है कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं।

नई सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने वादों को पूरा करे: तेजस्वी यादव

पटना/भाषा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विपक्षी दलों का कोई प्रमुख नेता शामिल नहीं हुआ।

तेजस्वी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट कर नीतीश कुमार को बधाई दी। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं। राजद नेता ने कहा, आशा है कि नई सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद शपथ लेने वाले अन्य 26 मंत्री में जदयू से विजय चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी (विधान परिषद के सदस्य), सुनील कुमार, लेशी सिंह, मदन सहनी, मोहम्मद जामा खान। भाजपा से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, राम कृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, नारायण प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, अरुण शंकर प्रसाद और डॉ. प्रमोद कुमार (विधान परिषद के सदस्य) ने मंत्री पद की शपथ ली। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) से संतोष सुमन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) से दीपक प्रकाश के साथ साथ लोजपा (रामविलास) से संजय कुमार और संजय कुमार सिंह हैं।

बिहार में नीतीश सरकार स्थिरता और विकास का नया अध्याय लिखेगी: रघुवर दास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जमशेदपुर/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार राज्य में स्थिरता, विकास और सुशासन का एक नया अध्याय लिखेगी।

रघुवर ने नीतीश के 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर उन्हें बधाई दी। रघुवर ने कहा, नीतीश कुमार सरकार बिहार में स्थिरता, विकास और सुशासन का नया अध्याय लिखेगी। रघुवर ने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार में राजग सरकार विकास को गति देगी। नई बिहार सरकार 2047 तक देश को 'विकसित भारत' बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) सुप्रीमो नीतीश कुमार के अलावा उनकी पार्टी के आठ, भाजपा के 14 और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के दो विधायकों ने नई बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। जीतन राम माझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक-एक मंत्री ने भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली।

भारत के लिये हर प्रारूप खेल पाना आसान नहीं : यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। भारत के बायें हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने स्वीकार किया कि भारत में हर प्रारूप में खेलने का मौका मिलना आसान नहीं है लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच आक्रामक मानसिकता से वह अपनी जगह बनाये हुए हैं।

कुलदीप आस्ट्रेलिया में पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के बीच से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला खेलने स्वदेश लौट आये थे। उन्होंने पहले टेस्ट में चार विकेट लिये हालांकि भारत 30 रन से हार गया था। सभी प्रारूप मिलाकर 342 विकेट ले चुके कुलदीप ने जियो स्टार के ' फॉलो द ब्लूज' कार्यक्रम में कहा ,'' निश्चित तौर पर आप तीनों प्रारूप खेलना चाहेंगे लेकिन टेस्ट खेलने में मजा आता है। भारत में सभी प्रारूपों में खेल पाना आसान नहीं है।''

उन्होंने कहा ,''हर किसी को टेस्ट क्रिकेट पसंद है। सभी को इसमे मजा आता है लेकिन यह काफी चुनौतीपूर्ण भी है। अगले चार पांच साल टेस्ट क्रिकेट में मेरे लिये काफी अहम हैं तो मैं अपनी फिटनेस बनाये रखने और इसी तरह से खेलने पर फोकस करूंगा।'' उन्होंने कहा कि अपनी भूमिका को लेकर वह स्पष्ट है और टीम प्रबंधन के सहयोग से वह आक्रामक मानसिकता के साथ खेल पाते हैं। कुलदीप ने कहा ,'' एक आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर मैं काफी स्पष्ट हूं। मुझे अपनी भूमिका पता है। कोच और कप्तान ने काफी स्पष्टता और सहयोग दिया है। मैं हमेशा आक्रामक मानसिकता से खेलता हूं और मेरा काम विकेट लेना है।

धोखेबाजी के जरिये बनाये गए जनाधार को बचाने की कोशिश कर रही हैं ममता : भाजपा

नई दिल्ली/भाषा। भाजपा ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ शिकायत कर रही हैं क्योंकि उनका राजनीतिक वजूद ''धोखेबाजी के जरिये'' बनाये गए जनाधार को ''बचाने'' पर टिका हुआ है। भाजपा की यह प्रतिक्रिया एसआईआर को लेकर बनर्जी द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखे जाने के बाद आई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सीईसी को लिखे बनर्जी के पत्र को ''हताशा का संकेत'' बताया और उन पर आरोप लगाया कि वह उस परिवेश को बचाने के लिए एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रही हैं ''जिसने उन्हें सत्ता में बनाए रखा है।'' उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, ''एसआईआर प्रक्रिया को रोकने के लिए ममता बनर्जी का निर्वाचन आयोग को पत्र लिखना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि (तृणमूल) शीर्ष नेतृत्व घबरा गई हैं।

नीतीश कुमार: हर बार 'फीनिक्स' की तरह उठ खड़े होने वाले जुझारू नेता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। करीब 50 वर्षों के अपने राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार ने हर बार संदेह और आलोचना के दौर से उबरकर 'फीनिक्स' की तरह फिर से उठ खड़े होने की अद्भुत क्षमता दिखाई है।

मंडल राजनीति के बाद उभरने वाले नेताओं में सबसे अलग रहे नीतीश कुमार ने प्रशासनिक कमियों को दूर करने की दक्षता दिखाई, जबकि उन्हीं के समय के कई नेता इस मामले में पीछे रह गए। आलोचक अक्सर उन पर अवसरवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। इसे राजनीतिक अवसरवाद कहें या दूरदर्शिता, नीतीश की रणनीति की वजह से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अब तक राज्य में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बहुत मजबूत है और हालिया विधानसभा चुनाव में 89 सीट जीती है, जबकि जनता दल यूनाइटेड (जदयू) को 85 सीटें मिलीं। कुमार देश के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले 10 मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। वह कुल 19 वर्षों से सत्ता में हैं। राजनीतिक पाला बदलने की आदत के कारण उन्हें आलोचक और विरोधी दलों के नेता 'पलटू राम' कहने लगे, जबकि सुशासन के लिए उनकी लोकप्रियता 'सुशासन बाबू' के नाम से भी है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जदयू ने भाजपा से बेहतर 'स्ट्राइक रेट' दर्ज किया। दोनों ने बराबर सीटें जीतीं, जबकि जदयू ने एक कम सीट पर चुनाव लड़ा था। केंद्र में बहुमत न होने के कारण भाजपा गठबंधन के इस सहयोगी दल पर निर्भर है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद और जेपी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने के पश्चात, कुमार ने राज्य बिजली विभाग की नौकरी ठुकराकर राजनीति में कदम रखा।

तृणमूल सांसद ने बंगाल में 'निष्क्रिय' आधार नंबरों की यूआईडीएआई सूची पर सवाल उठाए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने बृहस्पतिवार को सवाल उठाया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पश्चिम बंगाल के 'निष्क्रिय' आधार नंबरों की सूची भारत निर्वाचन आयोग के साथ कैसे साझा की और कहा कि उसने पहले दावा किया था कि ऐसी सूची नहीं रखी जाती हैं। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य गोखले ने आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग वोट चोरी के लिए मोदी सरकार के यूआईडीएआई के साथ मिलकर काम कर रहा है। गोखले ने कहा, कुछ दिन पहले यह रिपोर्ट आई थी कि यूआईडीएआई (जो आधार जारी करता है) ने ईसीआई के साथ 30-32 लाख निष्क्रिय आधार नंबर साझा किए हैं। यूआईडीएआई का दावा है कि ये आधार नंबर उन लोगों के हैं जिनकी मौत हो चुकी है।

हरदोई के एक स्कूल में गैस रिसाव होने से 16 छात्र बेहोश, जांच के आदेश

हरदोई/भाषा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला कस्बे के एक निजी स्कूल में संदिग्ध रूप से गैस रिसाव की चपेट में आने से कम से कम 16 छात्र बेहोश हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सभी प्रभावित बच्चों को दो निजी अस्पतालों में ले जाया गया, जहां से एक बच्चे को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ भेज दिया गया। जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और रिसाव के कारण की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के मुताबिक, स्कूल परिसर में गैस की तेज गंध फैल गई, जिससे कई बच्चे घबरा गए और अपनी कक्षाओं से बाहर भाग निकले। शिक्षकों ने तुरंत सभी विद्यार्थियों को बाहर निकाला और अभिभावकों व प्रशासन को सूचित किया। जिलाधिकारी झा और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और इलाज करा रहे बच्चों से भी मिले।

अगर वे घास काटेंगे तो इससे अंतर पैदा होगा : पीट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी कोच पीट बोथा को लगता है कि बरसापारा स्टेडियम का विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतर होगा लेकिन वह यह जानना चाहते हैं कि क्या भारतीय क्यूरेटर लाल मिट्टी वाली पिच से घास हटा देंगे।

दूसरा और आखिरी टेस्ट शनिवार से यहां शुरू हो रहा है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स की मुश्किल पिच पर हार के बाद भारत 0-1 से पीछे है।

बोथा ने दूसरे टेस्ट से पूर्व संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, ''जहां तक पिच का सवाल है तो मैंने आज सुबह इसे देखा। अभी दो दिन बाकी हैं इसलिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वे असल में और घास काटेंगे या नहीं। इससे जाहिर तौर पर फर्क पड़ेगा।''

प्रथम श्रेणी में 217 विकेट चटकाने वाले बोथा ने कहा, ''लेकिन हमने जो सुना है उसके हिसाब से यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट होगा और स्पिन की भूमिका बाद में बनेगी। लेकिन हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि शायद स्पिन पहले होने लग जाए जैसे पिछले टेस्ट में हुआ था।''

बोथा का मानना था कि भारत में सामान्य समय से आधा घंटा पहले सुबह नौ बजे मैच शुरू होने से नमी की वजह से नई गेंद की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा, ''मैच नौ बजे शुरू हो रहा है, ज़ाहिर है यह थोड़ा ठंडा होगा। रात में काफी गर्मी होती है लेकिन जाहिर है थोड़ी अधिक नमी होगी इसलिए मुझे लगता है कि पहले घंटे में नई गेंद की भूमिका होनी चाहिए। कितने देर तक, हमें पक्का नहीं पता, हमें देखना होगा।''

बोथा ने कहा, ''अगर विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा है तो पहले बल्लेबाजी करना एक अच्छा विकल्प है लेकिन अगर विकेट कोलकाता जैसा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।'' उन्होंने कहा, ''अगर गेंद पहले दिन से ही टर्न होने लगे तो कभी-कभी इसकी (पहले बल्लेबाजी करने की) कोई खास भूमिका नहीं होती क्योंकि यह पिछले मैच की तरह कम स्कोर वाला मैच बन जाता है और फिर पहले, दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने की उतनी बड़ी भूमिका नहीं होती।''

बोथा ने कहा, ''लेकिन अगर पिच पहले दो दिन ठीक-ठाक खेलने वाली है तो आप जाहिर है कि पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे जिससे कि बाद में परिस्थितियों का फायदा उठा सकें।''

हर कोई गंभीर को दोष दे रहा है, कई बार एजेंडा जैसा लगता है : कोटक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की हार के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर की आलोचना से आजिज आ चुके भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ लोग निहित स्वार्थों के कारण ऐसा कर रहे हैं।

पिछले एक साल में गंभीर के कोच रहते भारत ने चौथा टेस्ट गंवाया है। कोटक ने शनिवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट से पहले कहा ,'' गौतम गंभीर, गौतम गंभीर (आलोचना) हो रहा है। मैं इसलिये ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मैं स्टाफ हूं और मुझे बुरा लग रहा है। यह कोई तरीका नहीं है।' उन्होंने कहा कि कई बार लगता है कि आलोचना एजेंडे के चलते हो रही है। सौराष्ट्र के पूर्व खब्बू बल्लेबाज ने कहा ,'' शायद कुछ लोगों का व्यक्तिगत एजेंडा है। उन्हें शुभकामनायें लेकिन यह बहुत खराब है।'' कोलकाता में पहले टेस्ट के लिये इस्तेमाल की गई पिच को लेकर भी गंभीर की आलोचना हो रही है। भारतीय टीम 124 रन के साधारण लक्ष्य का पीछा करते हुए भी हार गई। गंभीर ने बाद में यह भी कहा कि पिच वैसी ही थी, जैसी मांगी गई थी। वहीं कुछ सप्ताह पहले शुभमन गिल ने कहा था कि भारतीय टीम अच्छी पिचों पर खेलना चाहती है जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों की मदद करे। कोटक ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि गंभीर के अलावा किसी से सवाल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा,'' कोई यह नहीं कह रहा कि बल्लेबाजों ने यह किया या गेंदबाजों ने गलती की या हम बल्लेबाजी में कुछ और कर सकते थे।'' उन्होंने यह स्वीकार करने के लिये गंभीर की सराहना की कि उन्होंने ऐसी ही पिच मांगी थी। उन्होंने कहा,'' पिछले मैच में गंभीर ने सारा दोष खुद पर ले लिया। उसने कहा कि उसने ऐसा इसलिये किया क्योंकि उसे लगा कि क्यूरेटरों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये।'' कोटक का मानना है कि पिछले 15 साल में तकनीक और मानसिकता में बदलाव टी20 क्रिकेट अधिक खेले जाने से आया है। उन्होंने कहा ,'' अब दुनिया भर में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो तीनों प्रारूप खेलते हैं लेकिन तीनों प्रारूपों में खेलने की तकनीक अलग अलग होती है। टेस्ट मैच में फुटवर्क पर काफी जोर रहता है और टी20 में पावर हिटिंग अहम है जिसमें फुटवर्क की उतनी भूमिका नहीं होती।''

सुविचार

कर्म आपके कार्यों में नहीं, बल्कि आपकी इच्छा में होता है। आपके जीवन की घटनाएं नहीं; बल्कि उन घटनाओं के पीछे का संदर्भ कर्म पैदा करता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

मुसीबत का फंदा है यह प्रस्ताव

म्यांमार में ऑनलाइन ठगी के केंद्रों में नौकरी के लिए जाने वाले लोगों में से भारतीय नागरिकों की बड़ी संख्या चिंताजनक है। उसके म्यावाड्डी शहर स्थित इन केंद्रों से मुक्त करवाकर 125 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। ये लोग विदेश में अच्छी कमाई करने गए थे, लेकिन वहां इन पर मुसीबतें टूट पड़ीं। साइबर ठगों ने सोशल मीडिया पर जाल बिछा रखा है। वे बेरोजगार युवाओं को शिकार बनाते हैं। उन्हें मोटी कमाई और खुशहाल जिंदगी के सब्ज बाग दिखाकर विदेश बुलाते हैं। उसके बाद अपनी 'कैद' में रखते हैं। भारत के बेरोजगार युवा कितनी आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं, इसका अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इस साल मार्च से अब तक म्यांमार के ठगी केंद्रों से रिहा हुए कुल 1,500 भारतीय नागरिकों को थाईलैंड होते हुए स्वदेश लाया जा चुका है। युवाओं को पता होना चाहिए कि साइबर ठग उन्हें कथित नौकरी देने के नाम पर गुलाम बनाना चाहते हैं। म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता और अशांति का माहौल है। वहां ऐसी कौनसी नौकरी है, जिसे करने से भारतीय नागरिकों को लाखों रुपए की कमाई होगी? यह सवाल हर उस युवा के मन में जरूर उठना चाहिए, जो कमाई करने के लिए म्यांमार जाना चाहता है। उस देश की अर्थव्यवस्था बदहाल है, वहां कोई बड़ा उद्योग नहीं है, कई आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। अचानक म्यांमार के हाथ कौनसा खजाना लग गया कि वहां विदेशी नागरिकों को नौकरी करने के लिए बुलाया जा रहा है? जो भारतीय युवा वहां जाकर फंस गए, उन्हें पहले समाचार पत्रों और वेबसाइटों से पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी।

बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास की यह सलाह अत्यंत प्रासंगिक है कि 'भारतीय नागरिक विदेश में नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले विदेशी नियोक्ताओं की विश्वसनीयता तथा भर्ती एजेंट एवं कंपनियों की जांच कर लें।' म्यांमार का म्यावाड्डी शहर साइबर अपराधियों का गढ़ बन चुका है। वहां से पिछले महीने ही 28 देशों के 1,500 लोग थाईलैंड पहुंचे थे। पिछले दो वर्षों में साइबर ठगी संबंधी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। उनमें दिखाई दे रहे लोगों की भाषा, लहजे आदि का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि भारतीय नागरिकों के साथ पाकिस्तानी नागरिक भी इस धंधे में लगे हुए हैं। इसकी बड़ी वजह है- भाषा की समानता। साइबर ठग जानते हैं कि भारत में तेजी से डिजिटलीकरण हो रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लोग अपनी जमा-पूंजी बैंक खातों में रखते हैं। उन्होंने पिछले दो वर्षों में लोगों के खातों से लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक उड़ाए हैं। म्यांमार में साइबर ठगी के गिरोह चलाने वाले अपराधियों में कई चीनी नागरिक बताए जा रहे हैं। जो व्यक्ति उनके यहां 'नौकरी' करने जाता है, वे उसके साथ बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। वे ठगी के लिए टार्गेट देते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसे हासिल करने में नाकाम रहता है तो उसकी पिटाई तक कर देते हैं। एक भारतीय युवा, जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर स्वदेश लौटा था, ने बताया था कि जब वहां उसकी तबीयत खराब हुई तो न दवा दी गई, न खाना दिया गया। बस, यह दबाव डालते रहे कि 'टार्गेट पूरे करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लूटें!' भारत दो तरह से इन गिरोहों के निशाने पर है- वे भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन ठगी करते हैं, भारतीय युवाओं से यह अपराध करवाते हैं। इसके मद्देनज़र सरकार को डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत बनाने की जरूरत है। साथ ही, विदेश में नौकरी के लिए जाने वाले नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। जो कंपनी बुला रही है, उसके बारे में जानकारी जुटाएं और अन्य कर्मचारियों के अनुभव जानें। बिल्कुल ही अनजान और बहुत ज्यादा कमाई का वादा करने वाली विदेशी कंपनी पर विश्वास करना जोखिम भरा हो सकता है।

ट्वीटर टॉक

मीडिया द्वारा पूछने कि एसआईआर पर कांग्रेस कब आंदोलन करेगी पर जवाब : अब देखिए हाईकमान ने फैसला किया परसों, कल-परसों मीटिंग हुई है, जो फैसला सुनाया आपको मिस्टर वेणुगोपाल ने, कि तय किया कि पहला वीक जो है दिसंबर में उसमें रामलीला मैदान में रैली होगी।

-अशोक गहलोत

राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था आज जिस बदहाली से गुजर रही है, वह भाजपा सरकार की नाकामी और गलत नीतियों का जीता जागता प्रमाण है। सत्ता में आए सरकार को 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन प्रदेश की स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के हाल बेहद शर्मनाक हैं।

-गोविंद सिंह डोटासरा

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रथम सत्र को संबोधित किया। बदलते वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र की संरचना को समकालीन चुनौतियों के अनुरूप पुनर्संयोजित करने की आवश्यकता आज भी प्रासंगिक है।

-ओम बिरला

प्रेरक प्रसंग

तपस्या का हजारीबाग

बिहार के एक छोटे से गांव में हजारी नामक किसान अक्सर देखता था कि लोग हरे-भरे पेड़ों को उखाड़ फेंकते थे। जब पेड़ों पर कुल्हाड़ी का वार होता, तो वह बहुत दुखी होता। एक दिन उसने गांव के लोगों को एकत्रित कर कहा, 'अगर हम ऐसे ही पेड़ों को नष्ट करते रहे तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा।' जब हजारी को लगा कि लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, तो उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह प्रतिदिन खेत पर आते-जाते दो पौधे अवश्य लगाएगा और उनकी देखभाल भी करेगा। पहले लोगों ने उसे ऐसा करते देख मजाक उड़ाया, मगर जब उन्होंने देखा कि हजारी पर उनकी नकारात्मक बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो वे चुप हो गए। हालांकि, कुछ युवाओं ने हजारी का साथ देने का निश्चय किया और वे भी उसकी देखा-देखी पौधे लगाने लगे। इस तरह कुछ ही समय में वहां पर कई पेड़ लहलहाते नजर आने लगे और उस स्थान का कायापलट हो गया। हजारों पेड़ों की कतार यहां का प्रमुख आकर्षण बन गई। धीरे-धीरे इस स्थान को लोगों ने हजारी की अद्भुत तपस्या के कारण 'हजारीबाग' कहना शुरू कर दिया।

सामयिक

नक्सली माओवाद गिनता अंतिम सांसें

प्रमोद भार्गव
मोबाइल : 9981061100

छत्तीसगढ और आंध्रप्रदेश की सीमा पर हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने शीर्ष माओवादी क्रूर हिंसा के प्रतीक बन चुके हिड़मा को मार गिराने के बाद सात अन्य नक्सलियों को मार गिराने के साथ तय है, कि अब नक्सली हिंसा अपने अंतिम चरण में है। मार्च 2026 तक इसका समूल नाश हो जाएगा, क्योंकि अब प्रमुख नक्सली सरगनाओं की गिनती मात्र 3-4 तक सिमट गई है। यदि वे हथियार डालकर समर्पण नहीं करते हैं तो उनका भी अंत होना तय है। हालांकि इस मुठभेड़ में मप्र के बालाघाट में पदस्थ निरीक्षक आशीष शर्मा को बालिदान देना पड़ा है। माओवादी अर्से से देश में एक ऐसी जहरीली विचारधारा रही है, जिसे नगरीय बौद्धिकों का समर्थन मिलता रहा है। ये बौद्धिक नक्सली संगठनों को आदिवासी समाज का हितचिंतक मानते रहे हैं, जबकि जो आदिवासी नक्सलियों के विरोध में रहे, उन्हें इनकी हिंसक क्रूरता का शिकार होना पड़ा है। बावजूद इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि देश के वामपंथी दलों को कभी भी सुरक्षाबलों का नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा सफाये का अभियान पसंद नहीं आया। इससे पहले छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता तब मिली थी, जब डेढ़ करोड़ के इनामी बसव राजू समेत 27 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। यह कुख्यात दरिंदा होने के साथ गुरिल्ला लड़ाका था। माओवादी पार्टी का इसे पर्याय माना जाता था। इसका नक्सली सफर 1985 से शुरू हुआ था। इसने वारंगल के क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की थी।

नक्सली हिंसा लंबे समय से देश के अनेक प्रांतों में आंतरिक मुसीबत बनी हुई है। वामपंथी माओवादी उग्रवाद कभी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता रहा है। लेकिन चाहे जहां रक्तपात की नदियां बहाने वाले इस उग्रवाद पर लगभग नियंत्रण किया जा चुका है। नई रणनीति के अंतर्गत अब सरकार की कोशिश है कि सीआरपीएफ की तैनाती उन सब अज्ञात क्षेत्रों में कर दी जाएं जहां नक्सली अभी भी ठिकाना बनाए हुए हैं। इस नाते केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 4000 से अधिक सैन्यबल तैनात करने जा रहा है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च 2026 तक इस क्षेत्र को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए। इतनी बड़ी संख्या में सैन्यबलों की अज्ञात क्षेत्र में पहुंच का मतलब है कि अब इस उग्रवाद से अंतिम लड़ाई होने वाली है। मजबूत और कठोर कार्य योजना को अमल में लाने का ही नतीजा है कि इस साल सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में वर्ष 2024 में 153 नक्सली मारे जा चुके हैं। सह का कहना है कि 2004-14 की तुलना में 2014 से 2024 के दौरान देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है। 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा की 16,274 वारदातें दर्ज की गई थीं, जबकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 सालों में इन घटनाओं की संख्या घटकर 7,696 रह गई। इसी अनुपात में देश में माओवादी हिंसा के कारण होने वाली मौतों की संख्या 2004 से 2014 में 6,568 थीं, जो पिछले दस साल में घटकर 1990 रह गई हैं और अब सरकार ने जो नया संकल्प लिया हैए उससे तय है कि जल्द ही इस समस्या को निर्मूल कर दिया जाएगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आतंक और अलगाववाद खत्म करने की निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में अनुभव होने लगी है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली तंत्र कमजोर हुआ है, लेकिन उसकी शक्ति अभी शेष है। अब तक पुलिस व गुप्तचर एजेंसियां इनका सुराग लगाने में नाकाम होती रही थीं, लेकिन नक्सलियों पर षिकंजा कसने के बाद से इनको भी सूचनाएं मिलने लगी हैं। इसी का नतीजा है कि सैन्यबल इन्हें निशाना बनाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सली आदिवासी हैं। इनका कार्यक्षेत्र वह आदिवासी बहुल इलाके हैं, जिनमें ये खुद आकर नक्सली बने हैं। इसलिए इनका सुराग सुरक्षाबलों को लगा पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये इसी आदिवासी तंत्र से बने मुखबिरों से सूचनाएं आसानी से हासिल कर लेते हैं। दुर्गम जंगली क्षेत्रों के मार्गों में छिपने के स्थलों और जल स्रोतों से भी ये खूब परिचित हैं। इसलिए ये और इनकी शक्ति लंबे समय से यहीं के खाद-पानी से पोषित होती रही है। हालांकि अब इनके हमलों में कमी आई है। दरअसल इन वनवासियों में अर्बन माओवादी नक्सलियों ने यह भ्रम फैला दिया था कि सरकार उनके जंगल, जमीन और जल-स्रोत उद्योगपतियों को सौंपकर उन्हें बेदखल करने में लगी है, इसलिए यह सिलसिला जब तक थमता नहीं है, विरोध की मुहिम जारी रहनी चाहिए। सरकारें इस समस्या के निदान के लिए बातचीत के लिए भी आगे आईं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इन्हें बंदूक के जरिए भी काबू में लेने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन नतीजे पूरी तरह अनुकूल नहीं रहे।

एक उपाय यह भी हुआ कि जो नक्सली आदिवासी समर्पण कर मुख्यधारा में आ गए थे, उन्हें बंदूकें देकर नक्सलियों के विरुद्ध खड़ा करने की रणनीति भी अपनाई गई। इस उपाय में खून-खराबा तो बहुत हुआ, लेकिन समस्या बनी रही। गोया, आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने से लेकर विकास योजनाएं भी इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अब तक सफल नहीं हो पाई हैं।

इस मुठभेड़ में मारे गए हिड़मा का बस्तर के इस जंगली क्षेत्र में बोलबाला रहा है। वह सरकार और सुरक्षाबलों को लगातार चुनौती दे रहा था, जबकि राज्य एवं केंद्र सरकार के पास मोदी सरकार से पहले रणनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति की हमेशा कमी रही थी। तथाकथित शहरी माओवादी बौद्धिकों के दबाव में भी मनमोहन सिंह सरकार रही। इस कारण भी इस समस्या का हल दूर की कौड़ी बना रहा। यही वजह थी कि नक्सली क्षेत्र में जब भी कोई विकास कार्य या चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती थी तो नक्सली उसमें रोड़ा अटका देते थे। अब हिड़मा के मारे जाने के बाद नक्सली समस्या का हल की गुंजाइश बढ़ गई है। कांग्रेस की पूर्व केंद्र तथा छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार नक्सली समस्या से निपटने के लिए दावा कर करती रही हैं कि विकास इस समस्या का निदान है। यदि तत्कालीन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के विकास संबंधी विज्ञापनों में दिए जा रहे आंकड़ों पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर विकास के मानदण्डों को छूती दिख रही है, लेकिन इस अनुपात में यह दावा बेमानी है कि समस्या पर अंकुश विकास की धारा से लग रहा है, क्योंकि इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए जाने के प्रमाण भी मिले थे।

बावजूद कांग्रेस के इन्हीं नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीतकर आते रहे थे। हालांकि नक्सलियों ने कांग्रेस पर 2013 में बड़ा हमला बोलकर लगभग उसका सफाया कर दिया था। कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा ने नक्सलियों के विरुद्ध सलवा जुडूम को 2005 में खड़ा किया था। सबसे पहले बीजापुर जिले के ही कुर्तु विकासखण्ड के आदिवासी ग्राम अंबेली के लोग नक्सलियों के खिलाफ खड़े होने लगे थे। नतीजतन नक्सलियों की महेंद्र कर्मा से दुश्मनी ठन गई थी। इस हमले में महेंद्र कर्मा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और हरिप्रसाद समेत एक दर्जन नेता मारे गए थे। लेकिन कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी खोई शक्ति फिर से हासिल कर ली थी, बावजूद नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपदस्थ कर भाजपा फिर सत्ता में आई, उसके बाद से ही नक्सलियों के सफाए का सिलसिला चल रहा है।

दरअसल, देश में अब तक तथाकथित शहरी बुद्धिजीवियों का एक तबका ऐसा भी रहा, जो माओवादी हिंसा को सही ठहराकर संवैधानिक लोकतंत्र को मुखर चुनौती देकर नक्सलियों का हिमायती बना हुआ था। यह न केवल उनको वैचारिक खुराक देकर उन्हें उकसाने का काम करता था, बल्कि उनके लिए धन और हथियार जुटाने के माध्यम भी खोला था। बावजूद इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब ये राष्ट्रघाती बुद्धिजीवी पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए गए तो बौद्धिकों और वकीलों के एक गुट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभाव में लेने की कोशिश की थी और गिरफ्तारियों को गलत ठहराया था। माओवादी किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो भी उनके खिलाफ जाता है, उसकी बोलती बंद कर दी जाती हैं। लेकिन अब इस चरमपंथ पर पूर्ण अंकुश लगने जा रहा है।

नजरिया

लोकतंत्र की कसौटी पर चुनाव आयोग

महेन्द्र तिवारी
मोबाइल : 9989703240

भारतीय लोकतंत्र इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ संस्थागत साख और राजनीतिक जवाबदेही के बीच संघर्ष असाधारण रूप से तीखा हो गया है। हाल ही में 272 नागरिकों (पूर्व जजों, नौकरशाहों, राजनयिकों और सैन्य अधिकारियों) द्वारा जारी खुले पत्र ने इस संघर्ष को और अधिक स्पष्ट और संवेदनशील बना दिया है। पत्र में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं-विशेषकर चुनाव आयोग-की विश्वसनीयता को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। दूसरी ओर विपक्ष का तर्क है कि ये सभी हस्ताक्षरकर्ता सत्ता से कठिन सवाल पूछने का साहस नहीं कर पा रहे, जबकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर वास्तविक और गंभीर शंकाएँ मौजूद हैं। यह पूरा विवाद भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, संस्थागत पारदर्शिता और राजनीतिक संवाद की बदलती प्रकृति का दर्पण बन गया है।

नागरिकों के इस पत्र में कहा गया कि विपक्ष जानबूझकर सेना, न्यायपालिका, संसद और अब चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर हमला कर रहा है। पत्र में विशेष रूप से राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों पर सवाल उठाए गए, जिनमें उन्होंने दावा किया था कि उनके पास 100 प्रतिशत सबूत हैं, जबकि उन्हें न तो औपचारिक शिकायत के रूप में पेश किया गया, न हलफनामे के रूप में। पत्र में यह भी रेखांकित किया गया कि चुनाव आयोग की ड्खठ प्रक्रिया-जिसमें मतदाता सूची की समीक्षा, अवैध नामों को हटाना और पात्र मतदाताओं को जोड़ना शामिल है-पूर्णतः पारदर्शी और सार्वजनिक है। हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुसार, केवल राजनीतिक हार के आधार पर आयोग की भूमिका पर संदेह उठाना चयनात्मक आक्रोश है, क्योंकि जीत के समय कोई ऐसी आलोचना सामने नहीं आती। उनके अनुसार मतदाता सूची की पवित्रता बनाए रखना विश्व के किसी भी लोकतंत्र में अपरिहार्य है, और भारत को भी इसी सिद्धांत पर कायम रहना चाहिए।

परंतु कांग्रेस की प्रतिक्रिया उतनी ही तीखी और आरोपों से भरी थी। उनका कहना है कि यह पत्र वस्तुतः चुनाव आयोग की संभावित लापरवाही या पक्षपात पर उठ रहे सवालों से ध्यान हटाने का प्रयास है। कांग्रेस प्रवक्ता का यह तर्क कि 272 लोगों में से एक भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, और न ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने चुनावी प्रबंधन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई हो, इस पत्र की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। विपक्ष यह भी कहता है कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों, जैसे एक ही पते पर दर्जनों नाम, फर्जी पते, डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ और बिना फोटो पहचान के वोट देने की घटनाओं पर लगातार रिपोर्ट सामने आती रही हैं, फिर भी चुनाव आयोग ने इन मामलों को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता या सक्रियता नहीं दिखाई। यह प्रश्न इसलिए और जटिल हो जाता है क्योंकि लोकतंत्र में संस्थाओं को सम्मान देना जितना आवश्यक है, उनसे सवाल पूछना उतना ही अनिवार्य-और वैध-कदम है। केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं होता, लेकिन केवल आरोपों को खारिज कर देना भी किसी स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकेत नहीं कहा जा सकता। आधुनिक लोकतंत्र केवल निष्पक्ष होने से नहीं चलता; उसे निष्पक्ष दिखना भी पड़ता है। जब जनता का विश्वास किसी संस्था की ओर से डगमगाने लगता है, तब सवालों को संस्थाओं पर हमला' बता देना राजनीतिक दृष्टि से सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टि से यह खतरनाक संकेत माना जाएगा।

भारतीय राजनीति में बढ़ते ध्रुवीकरण ने इस विवाद को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। राजनीतिक दल जब अपने-अपने चश्मों से संस्थागत क्रियाकलापों को देखने लगते हैं, तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुँच पाना कठिन हो जाता है। विपक्ष की शिकायत है कि चुनाव आयोग अपने निर्णयों पर औपचारिक और तकनीकी रूप से पारदर्शी होते हुए भी राजनीतिक रूप से अप्रत्यक्ष दबावों से मुक्त दिखाई नहीं देता। वहीं सत्ता पक्ष और पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले नागरिकों का मत है कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए आयोग को कटघरे में खड़ा करना देश की लोकतांत्रिक संरचना को कमजोर करता है। यह दो तरह का अविश्वास है- एक तरफ संस्थाओं पर, और दूसरी तरफ विपक्ष की मंशा पर।

इस पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दोनों पक्ष आंशिक रूप से सही हैं, और दोनों ही लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा हैं। विपक्ष यदि यह कहता है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ हैं, तो इन दावों का स्वतंत्र ऑडिट किया जाना चाहिए। और यदि नागरिक समूह यह कहता है कि बिना सबूत आरोप लगाना संस्थागत साख को चोट पहुँचाता है, तो इसमें भी तर्क है। समस्या तब पैदा होती है जब कोई भी पक्ष अपने दावे को तथ्यों, औपचारिक शिकायतों और सत्यापित प्रक्रियाओं के बजाय भावनात्मक और राजनीतिक आरोपों पर आधारित कर देता है।

भारतीय लोकतंत्र की इस घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण तत्व सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि उस बहस का मूल चरित्र है। लोकतंत्र में संस्थाओं की रक्षा तभी संभव है जब वे जनता की नज़र में न केवल विश्वसनीय हों, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही के आधुनिक मानकों पर खरी उतरे। विपक्ष की आलोचना और नागरिकों की चिंताओं दोनों को संतुलित रूप से सुना जाना चाहिए। असली सवाल यह है कि क्या भारत अपनी लोकतांत्रिक परिपक्वता को इतना मजबूत रख सकेगा कि राजनीतिक जंग संस्थागत विश्वास को न कुचल दे। लोकतंत्र की शक्ति यही है कि उसमें विवाद होते हैं-पर उसका अस्तित्व तभी सुरक्षित रह सकता है, जब विवाद तथ्यों और नैतिक मर्यादा पर आधारित हों, न कि शोर या संदेह के ध्रुवीकरण पर।

भारतीय लोकतंत्र की इस घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण तत्व सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि उस बहस का मूल चरित्र है। लोकतंत्र में संस्थाओं की रक्षा तभी संभव है जब वे जनता की नज़र में न केवल विश्वसनीय हों, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही के आधुनिक मानकों पर खरी उतरे। विपक्ष की आलोचना और नागरिकों की चिंताओं दोनों को संतुलित रूप से सुना जाना चाहिए। असली सवाल यह है कि क्या भारत अपनी लोकतांत्रिक परिपक्वता को इतना मजबूत रख सकेगा कि राजनीतिक जंग संस्थागत विश्वास को न कुचल दे।

महत्त्वपूर्ण
Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

गौरव दिवस

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में 'जनजातीय गौरव दिवस 2025' (ट्राइबल प्राइड डे) सेलिब्रेशन के दौरान पारंपरिक कपड़ों में आदिवासी कलाकार।

नेहरू अभिलेखागार

सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे 35 हजार दस्तावेज

नई दिल्ली/भाषा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यों और पत्राचार के बारे में जानने के उत्सुक लोगों को अब महज एक क्लिक भर से ये सब उपलब्ध हो सकेगा क्योंकि 'जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड' (जेएनएमएफ) ने नेहरू से संबंधित लगभग 35,000 दस्तावेज और 3000 चित्रों को समेटकर एक बड़ा ऑनलाइन अभिलेखागार तैयार किया है।

जेएनएमएफ का कहना है कि 'नेहरू आर्काइव डॉट इन' पर नेहरू के संबंध में 1920 से 1960 के दशक तक के कई पहलुओं को समेटा गया है तथा इस पर कोई दस्तावेज मुफ्त में 'सर्च' और 'डॉउनलोड' किया जा सकता है।

जेएनएमएफ की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, ''कुल 100 वॉल्यूम को डिजिटल स्वरूप दिया गया है और इसमें किसी भी सामग्री को मुफ्त सर्च और डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें वास्तविक प्रिंट संस्करण भी डिजिटल सामग्री के साथ उपलब्ध हैं।''

उसका कहना है, ''यह ऑनलाइन संस्करण उन सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जो 1920 से 1960 के दशक तक के भारतीय इतिहास के किसी भी पहलू का अध्ययन करना चाहते हैं। ये वो साल थे जब नेहरू आज़ादी के आंदोलन के एक बड़े नेता थे और देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे।''

इस अभिलेखागार में लगभग 35,000 दस्तावेज और लगभग 3000 चित्र हैं। वॉल्यूम 44 के बाद से, यानी सितंबर 1958 से नेहरू के भाषण मूल रूप से हिंदी में और इनके अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध हैं।''

विरोध

कोलकाता में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसीजर का विरोध करते लोग।

भारत गरीबी कम करने के लक्ष्य को पाने की राह पर : यूनिसेफ

नई दिल्ली/भाषा। भारत 2030 की समयसीमा से पहले बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को हासिल करने की राह पर है। हालांकि, लाखों बच्चे अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पानी जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। यूनिसेफ ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

'द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2025: एंडिंग चाइल्ड पॉवर्टी आवर शेयर्ड इम्पेरेटिव' रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 20.6 करोड़ बच्चे-जो देश की बाल आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं-शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता सहित छह आवश्यक सेवाओं में से कम से कम एक तक पहुंच से वंचित हैं। रिपोर्ट में कहा गया, इनमें से एक-तिहाई से भी कम (6.2 करोड़) बच्चों की पहुंच दो या उससे अधिक बुनियादी सेवाओं तक नहीं है, और उन्हें दो या अधिक कमियों से उबरने के लिए अब भी सहायता की आवश्यकता है।

विश्व बाल दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 46 करोड़ बच्चों में से आधे से ज़्यादा बच्चों को अब बुनियादी सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन प्रगति अब भी एक जैसी नहीं है। यूनिसेफ ने कहा, भारत ने गरीबी कम करने की दिशा में तरक्की की है - जो 2030 के आखिर से पहले एसडीजी 1.2 को पाने की दिशा में आगे बढ़ने का एक मजबूत संकेत है - जबकि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बच्चों की भलाई में निवेश रुका हुआ है।

संस्था ने कहा कि गरीबी उन्मूलन में भारत की प्रगति बाल गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण रही है। राष्ट्रीय बहु-आयामी गरीबी सूचकांक का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में बताया गया है कि 2013-14 और 2022-23 के बीच 24.8 करोड़ भारतीय बहु-आयामी गरीबी से उबर गए, और राष्ट्रीय गरीबी दर 29.2 प्रतिशत से गिरकर 11.3 प्रतिशत हो गई।

सामाजिक सुरक्षा दायरे में भारी बढ़ोतरी देखी गई जो 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गई है। सामाजिक सुरक्षा की पहुंच 94 करोड़ नागरिकों तक हो गई है, जिसने इस बदलाव में काफी योगदान दिया है।

यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्कैफ्रे ने कहा, बच्चों में निवेश करने से ज्यादा बेहतर निवेश कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की दिखाती है कि असरदार कार्यक्रम को और तेज करने से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने और भारत के 'विजन 2047' तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि बच्चों की कुशलता में सुधार सिर्फ संसाधनों के बारे में नहीं है...यह हमारे हर फैसले में बच्चों को प्राथमिकता देने की सामूहिक इच्छा और नेतृत्व के बारे में है।

भारत ने द्वीपीय देशों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आग्रह किया

बेलेम (ब्राजील)/भाषा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने हेतु समन्वित वैश्विक प्रयासों का आह्वान करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा परिवर्तन और सामाजिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) एसआईडीएस मंच के उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय नेतृत्व सत्र में बुधवार को यादव ने आईएसए के माध्यम से द्वीपीय देशों को भारत के समर्थन को रेखांकित किया और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश के तेजी से विस्तार की ओर इशारा किया।

यादव ने कहा कि छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (एसआईडीएस) को आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, जलवायु संबंधी व्यवधानों और कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण 'अद्वितीय कमजोरियों' का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किफायती, स्वच्छ और लचीली ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ाने के लिए सामूहिक स्तर पर कार्रवाई आवश्यक है।

आईएसए एसआईडीएस मंच का उद्देश्य मानकीकृत खरीद, मिश्रित वित्त और स्थानीय क्षमता निर्माण के जरिये सौर प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक डिजिटल और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

यहां यूएनएफसीसीसी कॉप 30 के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय नेतृत्व सत्र में एसआईडीएस और आईएसए के सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि एक साथ आए।

आईएसए के माध्यम से द्वीपीय देशों को भारत के समर्थन को रेखांकित करते हुए यादव ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश के तेजी से विस्तार का विवरण दिया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''आज भारत की स्थापित विद्युत क्षमता 500 गीगावाट को पार कर चुकी है और इसमें से आधे से अधिक स्वच्छ ऊर्जा है।

धनुष के साथ और भी फिल्मों में काम करना चाहती हैं कृति सेनन

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री कृति सेनन और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष की जोड़ी जल्द ही बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। फैंस उनकी फिल्म 'तेरे इश्क में' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दर्शक इस जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं। फिल्म को आनंद एल राय ने निर्देशित किया है और हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने इसकी कहानी को लिखा है।

ए.आर. रहमान का संगीत और इरशाद कामिल के गाने इस फिल्म को और भी खास बना रहे हैं। एक इंटरव्यू में कृति सेनन ने इस फिल्म का अनुभव साझा किया।

उन्होंने बताया कि धनुष के साथ काम करना उनके लिए रोमांचक भरा अनुभव रहा। उन्होंने कहा, ''मैं हमेशा से धनुष के अभिनय और उनके काम की बड़ी प्रशंसक रही हूं। वह अभिनय के हर पहलू को गहराई से समझने वाले कलाकार हैं। उनका अभिनय और निर्देशन का अनुभव सीन को पर्दे पर सही तरीके से पेश करने में बहुत मदद करता है।''

कृति ने कहा, ''धनुष अपने किरदार में कई अलग-अलग भाव और पहलुओं को बहुत खूबसूरती से सामने लाते हैं। मुझ पर उनके साथ काम करने का बेहद उत्साह था, क्योंकि मुझे पता था कि धनुष के साथ काम करते हुए मैं अपनी कला और बेहतर तरीके से दिखा सकूंगी। हमने सेट पर एक-दूसरे को पहली बार देखा, लेकिन इसका असर अभिनय पर बिल्कुल नहीं पड़ा।'' कृति ने बताया कि फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो काफी गहराई वाले हैं, और ऐसे सीन तभी प्रभावशाली बनते हैं जब दोनों कलाकार एक-दूसरे से प्रेरणा लें और अपने अभिनय में उसे महसूस कर सकें। कृति ने कहा, जब कोई सीन अच्छा निकलता, तो हम दोनों एक-दूसरे की ओर देखकर कहते, 'यह सीन बहुत अच्छा हुआ।' मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मुझे धनुष के साथ और भी फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।

बाला साहेब ठाकरे के पोते ऐश्वर्य बनेंगे विलेन

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म इंडस्ट्री में नए चेहरों का आना हमेशा से दर्शकों का उत्साह बढ़ाता है, खासकर तब जब उन्हें बड़े स्तर की फिल्मों में मौका मिल रहा हो। इस कड़ी में इन दिनों फिल्म निर्देशक अली अब्बास जफर की आगामी एक्शन-रोमांस ड्रामा फिल्म की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि इसमें शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे विलेन के तौर पर नजर आने वाले हैं। यह खबर सामने आते ही फिल्म को लेकर दर्शकों में दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। इस फिल्म में 'सैयारा' फेम अहान पांडे और 'मुंज्या' फेम शरवरी वाघ हैं। इस फिल्म के बारे में आईएएनएस के एक करीबी सूत्र ने बताया, ''अली अब्बास जफर बड़े स्तर के एक्शन और भावनाओं से भरी कहानियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म में भी वह उसी दमदार निर्देशन का प्रदर्शन करेंगे।'' सूत्र का कहना है कि अहान पांडे और ऐश्वर्य ठाकरे के बीच होने वाला आमना-सामना दर्शकों के लिए बड़े पर्दे पर लड़ाई जैसा होगा। फिल्म को बड़े बजट के साथ बनाया जा रहा है। रोमांस कहानी के केंद्र में होगा और एक्शन पूरी फिल्म में उत्साह और रोमांच का माहौल बनाए रखेगा।

फिल्म को इस तरह शूट किया जा रहा है कि दर्शक कहानी में पूरी तरह जुड़ जाएं। इसमें न सिर्फ खूबसूरत लोकेशन और बड़े सेटस देखने को मिलेंगे, बल्कि एक से बढ़कर एक एक्शन सीक्वेंस भी होंगे जो दर्शकों को चौंकाने का काम करेंगे। अली अब्बास जफर इस फिल्म में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते। वह हर सीन को बड़े पैमाने पर शूट करने की तैयारी कर रहे हैं।सूत्र ने आगे बताया कि इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात स्टारकास्ट है। अली अब्बास जफर तीन ऐसे कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, जिनमें भविष्य का बड़ा सितारा बनने की क्षमता है।इससे पहले 17 नवंबर को एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें अहान पांडे इस फिल्म के लिए रोजाना चार से पांच घंटे की ट्रेनिंग लेते दिख रहे हैं, जिसकी शुरुआत पहले बॉक्सिंग से होती है और फिर धीरे-धीरे मार्शल आर्ट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इसमें शामिल हो जाती है।

'मस्ती 4' में काम करना सपने के सच होने जैसा : रुही सिंह

मुंबई/एजेन्सी

फिल्मी दुनिया में जब कोई नया कलाकार किसी बड़ी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनता है, तो उसके लिए यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं होता, बल्कि एक बड़ा मौका होता है, अपने हुनर को दिखाने का, लोगों तक अपनी पहचान पहुंचाने का और उन सितारों के साथ काम करने का, जिन्हें वे सालों से पर्दे पर देखते आए हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव एक्ट्रेस रुही सिंह का भी रहा, जिन्होंने आने वाली फिल्म 'मस्ती 4' में कई मशहूर अभिनेताओं के साथ काम किया है। यह फिल्म पहले से चर्चित 'मस्ती' फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, जिसकी वजह से लोगों में पहले ही काफी उत्साह है। रुही के लिए यह फिल्म सिर्फ एक कॉमेडी नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने का मौका भी है। रुही सिंह ने बताया कि 'मस्ती 4' की शूटिंग उनके लिए एक खास सफर था। फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड के जाने-माने नाम आफताब शिवदासानी, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और अरशद वारसी जुड़े हुए हैं। उनके साथ स्क्रीन शेयर करना शानदार अनुभव रहा। रुही सिंह ने कहा, ''हर अभिनेता अपनी एक अलग ऊर्जा लाता है, और यह फिल्म मेरे लिए सीखने का एक बेहतरीन मौका बनी। इस फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता और कलाकारों की टीम ने मुझे अधिक मेहनत करने की प्रेरणा दी।''

फिल्म में रुही की जोड़ी अभिनेता आफताब शिवदासानी के साथ है। आफताब के साथ काम करने को लेकर उन्होंने कहा, ''वह बहुत ही विनम्र और सादगी भरे इंसान हैं। मेरे परिवार के सभी सदस्य और दोस्त आफताब को पहले से पसंद करते आए हैं, इसलिए उनके साथ काम करने का मौका मिलना किसी सपने के सच होने जैसा है।'' इसके बाद उन्होंने बाकी कलाकारों की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ''रितेश देशमुख कमाल के अभिनेता हैं, जिनकी कॉमिक टाइमिंग और नेचुरल एक्टिंग सभी को प्रभावित करती है।'' विवेक ओबेरॉय के बारे में उन्होंने कहा कि स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी यादगार होती है और वे हर किरदार में गहराई जोड़ते हैं। इंटरव्यू के दौरान जब आईएएनएस ने उनसे पूछा कि इतने बड़े स्टारकास्ट वाली फिल्म में क्या उन्होंने अपने रोल को लेकर कभी चिंता की, इस पर रुही ने जवाब देते हुए कहा, मेरे लिए भूमिका छोटी या बड़ी होने का कोई मतलब नहीं है। अगर किरदार को ईमानदारी से निभाया जाए तो वह अपने आप दर्शकों पर प्रभाव छोड़ता है।

मैं इस फिल्म का हिस्सा इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि यह एक बड़े स्तर की फिल्म है, जिसे देखने लाखों लोग आएंगे, और मैं चाहती थी कि उन दर्शकों के बीच मेरा चेहरा और नाम पहचाना जाए। उन्होंने बताया कि अपने रोल को लेकर वे पूरी तरह खुश हैं और उन्होंने उस पर बहुत मेहनत भी की है। 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, तुषार कपूर, एलनाज नौरोजी, शाद रंधावा और अन्य कलाकार शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी ने किया है। यह 21 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी।

शिल्पा-मिथुन की ऑनस्क्रीन जोड़ी आज भी फेवरेट, फैंस की डिमांड पर की नौ फिल्में

मुंबई/एजेन्सी

1990 और 2000 के दशक के बीच बॉलीवुड में कई अभिनेत्री आईं और चली गईं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हैं। शिल्पा शिरोडकर उन्हीं में से एक हैं। अपनी खूबसूरती, अदाकारी और स्क्रीन पर सहज हाव-भाव के लिए प्रसिद्ध शिल्पा ने दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया। लोगों ने उनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ बेहद पसंद की। उन्होंने कुल नौ फिल्मों में मिथुन के साथ काम किया और हर बार दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने सराहा। शिल्पा शिरोडकर का जन्म 20 नवंबर 1973 को मुंबई में हुआ। उनके परिवार का फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर से गहरा ताल्लुक रहा है। उनकी दादी मीनाक्षी शिरोडकर मराठी फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री थीं और उनकी मां गंगू बाई भी अभिनय से जुड़ी थीं। इस तरह शिल्पा को बचपन से ही फिल्मों और अभिनय की दुनिया का अनुभव मिला। उनकी छोटी बहन नम्रता शिरोडकर भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं और 1993 में 'मिस इंडिया' का खिताब जीत चुकी थीं।

शिल्पा ने करियर की शुरुआत 1989 में फिल्म 'भ्रष्टाचार' से की। इस फिल्म का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था, जिन्होंने उन्हें मिथुन चक्रवर्ती और रेखा के साथ काम करने का मौका दिया। फिल्म में शिल्पा ने अंधी लड़की का किरदार निभाया। यह उनका पहला बड़ा ब्रेक था। हालांकि, इस फिल्म से उन्हें लोकप्रियता तो नहीं मिली, लेकिन उनके टैलेंट की सराहना हुई।

उन्हें पहचान 1990 में आई 'किशन कन्हैया' से मिली। इस फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेता अनिल कपूर थे और शिल्पा ने राधा का किरदार निभाया। दर्शकों ने उनके अभिनय को पसंद किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी दौरान शिल्पा और मिथुन की जोड़ी पहली बार नजर आई और उनके बीच की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब भाई। इसके बाद शिल्पा ने कई हिट फिल्मों में काम किया। इनमें 'योद्धा', 'खुदा गवाह', 'आंखें', 'गोपी किशन', 'बेवफा सनम' और 'मृत्युदंड' जैसी फिल्में शामिल हैं। मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों की सबसे पसंदीदा जोड़ी में से एक बन गई। दोनों ने साथ में कुल नौ फिल्मों में काम किया और हर बार उनकी परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई। शिल्पा ने अपने करियर में कई पुरस्कारों के लिए नामांकन भी हासिल किए।

उन्हें 1993 में फिल्म 'खुदा गवाह' में उनके रोल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नामांकित किया गया। उनकी मेहनत, दमदार अभिनय और स्क्रीन पर सहज अंदाज ने उन्हें दर्शकों के बीच खास पहचान दिलाई। साल 2000 में शिल्पा ने यूके के बैंकर अपरेश रंजीत से शादी कर इंडस्ट्री से दूरी बना ली। इसके बाद उन्होंने करीब 13 साल तक अभिनय से ब्रेक लिया और परिवार के साथ समय बिताया। हालांकि, साल 2013 में उन्होंने टीवी शो 'एक मुट्ठी आसमान' के जरिए छोटे पर्दे पर वापसी की और फिर कई अन्य टीवी शोज में भी नजर आईं। वह कलर्स चैनल के रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' में भी बतौर कंटेस्टेंट नजर आईं, लेकिन फिनाले से कुछ पहले टॉप 6 में रहते हुए बाहर हो गईं।

कर्म पर करें पूरा फोकस, परिणाम पर नहीं : रवीना

नई दिल्ली/एजेन्सी

90 के दशक की एक्ट्रेस रवीना टंडन आज भी फिल्मों से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक छाई हुई हैं। एक्ट्रेस जल्द ही अक्षय कुमार के साथ 'वेलकम टू द जंगल' में दिखने वाली हैं, लेकिन इसी बीच रवीना ने सिंपल और अच्छी लाइफ जीने के लिए भगवद गीता के कुछ अनमोल वचन शेयर किए हैं। अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपना इंस्टाग्राम अपडेट किया है और भगवद गीता के अच्छे वचनों को शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, अपने कर्म पर पूरा फोकस करें, ये जाने बिना कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। कर्म पर फोकस करें न कि उसके रिजल्ट पर। दूसरे पोस्ट में लिखा, जीत होने पर ज्यादा खुशी जाहिर न करें और अपनी हार पर ज्यादा दुखी न हों, जिंदगी को संतुलन के साथ चलाएं।

एक अन्य पोस्ट पर लिखा है, ईमानदारी और दयालुता ही इंसान की असली ताकत होती है, हमेशा वहीं चुनें जो सही है, न कि सरल। फैंस को भी एक्ट्रेस के ये विचार काफी पसंद आ रहे हैं। रवीना टंडन एक्ट्रेस होने के समाज सेविका भी हैं। वे अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पशु-पक्षियों पर दया दिखाने की अपील फैंस से करती हैं। दिल्ली में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में बंद करने के आदेश पर एक्ट्रेस ने अपनी भड़ास निकाली थी और फैसले को असंवेदनशील बताया था। उन्होंने कहा था कि कुत्तों को शेल्टर होम में बंद कर देना कोई स्थाई समाधान नहीं है। इसके बदले आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने के बाद उन्हें छोड़ देना चाहिए।

रवीना टंडन को इसी महीने टेलीविजन सीरीज 'कर्मा कॉलिंग' में निगेटिव भूमिका के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार से नवाजा गया। इससे पहले उन्हें साल 2022 में भी 'अरण्यक' वेबसीरीज के लिए भी दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। उन्होंने सीरीज में कस्तूरी डोगरा के किरदार के लिए ये अवॉर्ड जीता था। उन्होंने अपने करियर में तमाम अवॉर्ड जीते हैं इतना ही नहीं। उनकी बेटी राशा टंडन भी फिल्मों में कदम रख चुकी हैं।

गौसेवा — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

चेन्नई में नेरकुन्डर्म ग्रुप द्वारा गुरुवार को आयोजित मासिक अमावस्या गौसेवा का आयोजन पर हरा चारा सुधारने की स्वचलित मशीन सन्मति गौशाला आवडी में भेंट की गई। ग्रुप के सदस्य धर्माराम, दुर्गाराम, भंवरलाल, दशरथ,देवराज, मुन्नाराम, महेंद्र,प्रकाश, रामदयाल, धर्माराम, प्रेम का राहुल नाहर द्वारा स्वीकृत कर अभिनन्दन किया गया।।

बीजेएस के मेले में बच्चों से उत्साह से भाग लिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सेलम। यहां भारतीय जैन संगठन (बीजेएस) सेलम चैप्टर द्वारा पहली बार गुजराती हॉल में विद्या धन मेला 'द फन फिएस्टा फेस्टिवल' में समाज के 40 बच्चों ने उत्साहपूर्वक अपने अपने गेम्स स्टॉल लगाए। 10 से 20 वर्ष आयु वर्ग के इन बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में लेन-देन, सहभागिता, जिम्मेदारी और सीखने की भावना विकसित करना था, जिसे उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ अनुभव किया। बीजेस सेलम ने सम्मानित सदस्यों, सहयोगियों और प्रायोजकों का सम्मान किया। जिनके सहयोग से यह ऐतिहासिक आयोजन सफल रहा। बीजेस के कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों और कार्यक्रम में विभिन्न रूप से सहयोग करने वालों का सम्मान किया। दीपा सक्रिय, आरती राठौर, नवीन जैन, पिंकी गुर्जर, राजेश भंसाली, विकास सक्रिय, अनिल पिंचा, प्रवीण बोकाडिया और अन्य सभी साथी सदस्यों ने भी उत्साहपूर्वक सहयोग किया। बीजेस संगठन अध्यक्ष अनिल जैन लेडीज़ विंग अध्यक्ष पिंकी, कोषाध्यक्ष निकेश जैन, तथा भवानी रीज़न उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन में संघ के कर्मठ सदस्य-तरुण शाह, राजू रंक, सीमा, रेखा, संदीप, मनीषा, चारु, यशोदा, ममता, अल्प और नरेंद्र ने अल्प समय में अद्भुत व्यवस्था एवं शानदार समन्वय किया।

रजत द्वारा तीन अनाथालय में सहयोग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां राजस्थानी एसोसिएशन तमिलनाडु (रजत) की अनुकम्पा समिति द्वारा तंडियारपेट स्थित करूणालय बाल गृह में अल्पाहार तथा पार्क टाउन स्थित चेन्नपुरी अन्नदान समाज में सुभाष चंद रांका परिवार के सहयोग से अल्पाहार परोसा गया। वहीं चेतपेट स्थित सर्वोदया गर्ल्स हॉस्टल में करीब 80 अनाथ लड़कियों को दोपहर का भोजन मोहनलाल बजाज परिवार के सहयोग से करवाया गया। वितरण कार्य में अध्यक्ष नरेन्द्र श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में अनुकम्पा चेयरमेन एफ. अजीत कुमार चोरडिया, सह चेयरमेन ज्ञानचंद कोठारी, रमेश खटोड़, सुमेर बैद, ललित रांका, जीतु भाई, राजेन्द्र कलानी, गणपत कोठारी ने सेवाएं प्रदान की।

भारत के प्रौद्योगिकी बदलाव के लिए भरोसेमंद, जिम्मेदार एआई का इस्तेमाल जरूरी : गूगल इंडिया प्रमुख

नई दिल्ली/भाषा। भारत के प्रौद्योगिकी बदलाव के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) का जिम्मेदारी तथा भरोसे के साथ इस्तेमाल बहुत जरूरी है और इस काम में शामिल सभी हितधारकों का दायित्व है कि वे सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करें। गूगल इंडिया की देश प्रबंधक प्रीति लोबाना ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। उन्होंने 'विकसित भारत' की ओर देश के कदम का जिक्र करते हुए कहा कि एआई इस सफर में एक जरूरी नींव का काम करेगा, और इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए भरोसा और सुरक्षा जरूरी हैं।

लोबाना ने यहां गूगल के 'सेफ एंड ट्रस्टेड एआई' कार्यक्रम में कहा, ''एआई को सच में अपनाने और रोजाना इस्तेमाल में लाने के लिए, हम सभी की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यह सुरक्षित और भरोसेमंद हो।'' उन्होंने कहा कि एआई एक बदलाव लाने वाली प्रौद्योगिकी है जो इंसानी काबिलियत को सामने लाएगी, और भारत पीछे न रहते हुए इस क्रांति की अगुवाई कर रहा है।

देश की विविधता का जिक्र करते हुए लोबाना ने कहा, ''भारत की जटिलता दुनिया को यह दिखाएगी कि तकनीक कैसे बड़े पैमाने पर असर डाल सकती है और यहां तक कि सबसे मुश्किल प्रणालीगत मुद्दों को भी हल कर सकती है।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई एक बड़ी छलांग का वादा करता है, लेकिन तरक्की भरोसे और सहयोग की नींव पर होनी चाहिए।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति की बैठक सम्पन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/तिरुपति। भारत सरकार के कार्यालयों में राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रयोग का जायजा लेने हेतु गठित संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा 20 नवम्बर को तिरुपति में भारतीय खाद्य निगम, मंडल कार्यालय चेन्नई का राजभाषायी निरीक्षण की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति के संयोजक सांसद उज्ज्वल रमण सिंह नेतृत्व में एवं अन्य सांसदों के उपस्थिति में बैठक संपन्न की गई।

बैठक में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, खाद्य मंत्रालय से राजेंद्र कुमार, संयुक्त निदेशक; नरेश कुमार, उप निदेशक(राजभाषा); भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली से जयंत शर्मा, कार्यकारी निदेशक(राजभाषा); ओ पी डानी, मुख्य महाप्रबंधक(राजभाषा) एवं हरिमोहन दीक्षित, उप महाप्रबंधक(राजभाषा); आदि उपस्थित थे। चेन्नै में राजभाषा हिंदी के प्रयोग व कार्यान्वयन को संतोषजनक पाया गया, जिसके तहत निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

मुलाकात — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

कोयम्बटूर में जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजपाल जैन को तेरापंथ महिला मंडल की सदस्याओं ने मुलाकात की और उन्हें 'धर्मचक्र के प्रवर्तक' पुस्तक भेंट की।

राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के घोड़े : भारत की घुड़सवार विरासत के जीते-जागते प्रतीक

नई दिल्ली/भाषा। भारत के राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में शामिल मशहूर घोड़े विराट, विक्रांत, एब्सोल्यूट, अर्जुन और ग्लोरियस केवल सामान्य अश्व नहीं हैं, बल्कि देश की घुड़सवार सैन्य विरासत की जीती-जागती मिसाल हैं। इन घोड़ों का अनुशासन, शान और उनकी पक्की वफादारी 'प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड' (पीबीजी) के उसूलों को दिखाती है। पीबीजी भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, जिसे 1773 में तत्कालीन गवर्नर-जनरल के अंगरक्षक (बाद में वायसराय के अंगरक्षक) के तौर पर बनाया गया था। पीबीजी प्रतिवर्ष लगभग 70 घुड़सवार सैन्य परेड और विस्तृत अभ्यास करते हैं। इनमें तीन मुख्य आयोजन शामिल हैं : गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग द रिट्रीट और संसद की शुरूआत (जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं।रेजिमेंट के कमांडेंट, कर्नल अमित बेरवाल ने बुधवार को बताया कि इनके अलावा पीबीजी द्वारा साप्ताहिक रूप से होने वाली औपचारिक गार्ड परिवर्तन परेड और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्राध्यक्षों को एस्कॉर्ट करना भी शामिल है, जिसके माध्यम से उन्हें भारत की संस्कृति, गौरव और आतिथ्य का प्रदर्शन किया जाता है।

राष्ट्रपति भवन में भारत के सबसे विशिष्ट घुड़सवार सैनिकों और उनके 'अश्व योद्धाओं' की विरासत के बारे में जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इन घोड़ों की हर उपस्थिति अनुशासन, परंपरा और भव्य प्रदर्शन का एक सहज मिश्रण होती है, जिसे पूरे भारत और दुनिया भर में लाखों लोग देखते हैं। एक मीडिया संवाद में बेरवाल ने पीबीजी की अश्व परंपरा का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया, दैनिक प्रशासन और औपचारिक कद शामिल थे।

पीएमवीबीआरवाई जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 18 नवंबर को चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ (समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के सदस्यों के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सत्र का नेतृत्व रंजय मूशाहरी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-ख, क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई एवं पुदुचेरी ने किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीबीआरवाई) के उद्देश्यों, लाभों और कार्यान्वयन ढाँचे के बारे में बताया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने और निर्यात क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बीच अनुपालन को बढ़ावा देने में इस योजना की भूमिका पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, क्षेत्रीय प्रभाग, चेन्नई के समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के संयुक्त निदेशक जयबल ए. ने भाग लिया, जिन्होंने ईपीएफओ के प्रयासों की सराहना की और समुद्री उत्पाद क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने में सहयोग का आश्वासन दिया।

चेन्नई उत्तर के सहायक भविष्य निधि आयुक्त बिपिन कुमार, ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ के प्रतिनिधि और अन्य हितधारकों ने इस संवादात्मक सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया।

कार्यक्रम का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ जिसमें पीएमवीबीआरवाई के अंतर्गत नामांकन और संचालन प्रक्रियाओं से संबंधित प्रतिष्ठान-स्तरीय प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

कोयम्बटूर में होगा बीजेएस का राज्याधिवेशन

राज्य कार्यकारिणी बैठक में हुए कई विषयों पर विचारविमर्श

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चिदम्बरम। भारतीय जैन संघटना (बीजेएस) तमिलनाडु की दूसरी राज्य कार्यकारिणी की बैठक चिदंबरम में 19 नवम्बर को संपन्न हुई। राज्याध्यक्ष कमल किशोर तातेड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक की शुरुआत बीजेएस की महिला विंग की सदस्यों द्वारा नमस्कार महामंत्र के साथ हुई।

बीजेएस चिदम्बरम के अध्यक्ष मनीष छल्लानी ने सभी का स्वागत और अभिनंदन किया और चिदम्बरम को यह मीटिंग आयोजित करने का अवसर प्रदान करने हेतु राज्य कार्यकारिणी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

राज्याध्यक्ष कमल किशोर तातेड़ ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेएस तमिलनाडु का हर कार्यकर्ता जिस निःस्वार्थ भाव से जैन समाज के उज्वल एवं सक्षम भविष्य के लिए कार्य कर रहे है वह सराहनीय है। राज्य महासचिव राजेश पोकरना ने गत बैठक की रिपोर्ट पटल पर रखी जिसे सर्वसहमति से पारित किया गया। उन्होंने अब तक की तमिलनाडु के चैप्टर द्वारा क्या कार्य किए गए उसकी जानकारी प्रदान की एवं समीक्षा की गई, भविष्य के कार्यों के बारे में चिंतन मंथन किया गया।

बीजेएस तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद आंचलिया ने तमिलनाडु स्तर पर जैन समाज की जरूरत को ध्यान रखते हुए कुछ कार्य करने की अपील की एवं महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष, सचिव ने अपने विचार रखे। प्रोग्राम हेड को उनके कार्यक्रमों में हो रहे बदलाव की जानकारी निवर्तमान अध्यक्ष रमेश पटावरी द्वारा विस्तार से दी गई। सभी प्रोग्राम हेड्स ने भी अपने अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की।र ाज्य उपाध्यक्ष मोनिका जैन एवं बीजेएस तमिलनाडु लेडीज विंग अध्यक्ष सरला बरडिया ने तमिलनाडु जैन नारी शक्ति को समाज के लिए कैसे जोड़ा जा सकता है उस पर अपनी अभिव्यक्ति दी।

बैठक में राज्य अधिवेशन के लिए कोयंबतूर चैप्टर द्वारा निवेदन आया था। जिसे पदधिकारियों ने पारित किया और साथ ही राज्य अधिवेशन के आयोजन पर विस्तार से चिंतन मंथन हुआ और सभी ने अधिवेशन को जैन समाज के लिए विशेष उपयोगी और प्रभावशाली बने उस पर लक्ष्य करते हुए आयोजित करना है। तकनीकी प्रमुख धर्मेन्द्र सुराणा ने युवाओं को जोड़ने की अपनी एक योजना की जानकारी प्रदान की। रमेश पटावरी ने जन जन की सेवा की दृष्टि से एक विशेष कार्यक्रम की जानकारी दी। दोनों सुझावों पर कार्यकारिणी ने आगे बढ़ने का निर्णय किया। कावेरी रीजन सचिव इंद्रा कोठारी ने चिदम्बरम टीम के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

गुलाब जैसे सभी को एक समान सुगंध देते हैं साधु-संत : डॉ. वरुणमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। 'संत चलते-फिरते तीर्थ के समान होते हैं, जिनकी चरण-रज से तीर्थ भी पावन हो जाते हैं। साधु-संत गुलाब के कोमल और सुगंधित फूल के समान होते हैं, वे जहां भी जाते हैं, वहां ज्ञान, धर्म, प्रेम, भक्ति और सेवा की सुगंध समान भाव से वितरित करते हैं। जिस प्रकार गुलाब का पुष्प बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनी सुगंध देता है, उसी प्रकार साधु-संत, अमीर-गरीब, शिक्षित-अनभिज्ञ, बड़े-छोटे सभी को समभाव से कृपा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।' ये विचार डॉ. वरुण मुनि जी ने कृष्णगिरि धाम में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संतों का प्रत्येक कदम लोक-कल्याणकारी होता है। वे नगर-नगर, ग्राम-ग्राम जाकर प्रवचन, सत्संग और धर्मप्रचार के माध्यम से प्रभु-भक्ति, नैतिकता, संयम और जीवन-मूल्यों की अमूल्य शिक्षा जन-जन तक पहुंचाते हैं। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रसंत उपप्रवर्तक पंकजमुनिजी, डॉ. वरुण मुनिजी व रूपेश मुनिजी वर्ष 2025 का गांधीनगर चातुर्मास संपन्न कर कृष्णागिरी तीर्थ धाम पहुंचे। रूपेश मुनिजी ने भावपूर्ण भजनों द्वारा सभा को भक्तिरस से सराबोर कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, तपस्या करने वालों, दान देने वालों और सेवा में तत्पर रहने वालों का अधिक से अधिक अनुमोदना करना ही उनकी विशेष भावना रहती है, जिससे समाज में प्रेरणा का संचार होता है।

मोदी ने धान की खेती में तमिलनाडु के प्रयासों की सराहना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि धान के क्षेत्र में तमिलनाडु की ओर से किया गया काम दुनिया भर में बेजोड़ है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन में किसानों के साथ बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। मोदी को बताया गया कि राज्य में धान की लगभग एक हजार पारंपरिक किस्में हैं, जिनका पोषण मूल्य मिलेट्स (मोटा अनाज) के बराबर है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि धान के क्षेत्र में तमिलनाडु द्वारा किया गया कार्य विश्व स्तर पर बेजोड़ है। बयान के अनुसार किसानों ने इस बात पर सहमति जताई और इस बात की पुष्टि की कि निर्यात किए जा रहे सभी धान, चावल और संबंधित मूल्यवर्धित उत्पादों को आयोजन स्थल पर प्रदर्शित किया गया है। प्राकृतिक खेती में लगे किसानों का अभिवादन करते हुए मोदी ने केले की उपज का अवलोकन किया और केले के अपशिष्ट के उपयोग के बारे में जानकारी ली।

एक किसान ने प्रधानमंत्री को बताया कि बड़ी संख्या में युवा सक्रिय रूप से खेती-बाड़ी को अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे लोग लगभग दो लाख रुपये प्रति माह कमाते हैं और उन्हें प्रेरणा के रूप में देखा जाता है।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.